₹ 1/-

हिंदी संस्करण

मनमहन सिंहः यादों का चिराग

एक देश, एक चुनावः क्या बदलेगा लोकतंत्र का चरित्र?

रूस की अर्थव्यवस्था पुतिन की सबसे बड़ी कमज़ोरी

CULT CURRENT

वर्षः8 अंकः 1 जनवरी, 2025

WE MAKE VIEWS

सपाट धरती के पैरोकारों का पाखंड

ई-पत्रिका

Let's
360°
Media Consultancy
Web solution
Advertising
Publication
Languages Services
Survey & Research
Branding
AV Production
Campaign management
Event organizer
PR partner, PR associate
Content writer & provider
Media analyst

URJAS MEDIA VENTUE IS PERHAPS THE ONLY CONSULTING FIRM THAT CAN GIVE YOUR ORGANISATION A 360 DEGREE MEDIA BUSINESS GROWTH CONSULTING THROUGH IT'S 360 CAPABILITIES. FOR US, CONSULTING DOES NOT ONLY MEAN MECHANICAL COST REDUCTION THROUGH BETTER IT APPLICATIONS, WE FIND OUT WHAT YOUR ORGANISATION REALY NEEDS AND GIVE YOU AN INTELLECTUAL SOLUTION THAT HELP YOU REDUCE COST AS WELL AS HELPS YOURS BUSINESS GROW AND BEAT THE COMPETITION.

NOW!! OUR CONSULTANT WILL GET BACK TO YOU IN 24 HOURS AND PUT YOU IN TO THE HIGH GROWTH PATH

URJAS MEDIA
VENTURE
BEAT THE COMPETITION
www.urjasmedia.com

SMS 'BUSINESS GROWTH'
TO +91-8826-24-5305 OR
E-MAIL info@urjasmedia.com

गुमनाम नायक

देसी बीजों का रखवाला

सलाई अरुण

80 हजार किलोमीटर घूमकर एक युवा किसान ने 300 दुर्लभ फल-सब्जियों के 300 प्रजातियों के बीज बचाएं हैं। यह कहानी है 32 साल के बीज रक्षक सलाई अरुण की। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मंगलम के रहने वाले अरुण ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर 300 से अधिक दुर्लभ सब्जियों का देसी बीज बैंक बनाया।

अरुण को बचपन से ही खेती से लगाव था छोटी उम्र में माँ को खोने के बाद वह अपने दादा-दादी के साथ पले-बढ़े और अक्सर अपने दादा को खेती में मदद किया करते थे। लेकिन खेती से उनका प्यार जुनून में तब बदला जब वह 2011 में जैविक कृषि वैज्ञानिक जी नम्मालवर से मिले अरुण ने उनसे ट्रेनिंग ली और एक्सपर्ट बनकर दूसरे किसानों को जैविक खेती सिखाने में लग गए। इस दौरान अरुण ने देखा कि किसानों के पास उगाने के लिए देसी सब्जियों के बीज हैं ही नहीं इसी चिंता के साथ साल 2021 में उन्होंने देशभर में घूमकर बीज इकट्ठा करने का मन बनाया।

संपादकीय टोली

संपादकीय

संपादकीय निदेशक
डॉ. विभाष श्रीवास्तव

संपादक
श्रीराजेश

राष्ट्रीय संपादक
संजय श्रीवास्तव

प्रबंध संपादक
सच्चिदानंद पाण्डेय

राजनीतिक संपादक
अंशुमान त्रिपाठी

मेट्रो संपादक
शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव

अंतर्राष्ट्रीय संपादक
श्रीश पाठक

कारपोरेट संपादक
गगन बत्रा

खेल संपादक
जलज श्रीवास्तव

डिजीटल संपादक
सुनीता त्रिपाठी

सहायक संपादक
संदीप कुमार

उप संपादक
मनोज कुमार
संतु दास

कला संपादक
जया वर्मा

वेब एवं आईटी विशेषज्ञ
अनुज कुमार सिंह

फोटो संपादक
विवेक पाण्डेय

विशेष संवाददाता
कमलेश झा
विकास गुप्ता

संवाददाता
संदीप सिंह
अनिरुद्ध यादव

ब्यूरो प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय)
अकुल बत्रा (अमेरिका)
सी.शिवरतन (नीदरलैंड)
जी. वर्मा(लंदन)
डॉ. मो. फहीम अकबर (पाकिस्तान)
ए. असगरजादेह (ईरान)
डॉ. निक सेरी (मलेशिया)

ब्यूरो प्रमुख (राष्ट्रीय)
आर. रंजन (नई दिल्ली)
संजय कुमार सिंह (लखनऊ)
कैप्टन सतीश सिन्हा (रांची)
निमेष शुक्ल (पटना)
नागेन्द्र सिंह (कोलकाता)
राकेश रंजन (गुवाहाटी)

विपणन
सत्यजीत चौधरी
महाप्रबंधक

ऑनलाइन प्रसार
सृजीत डे

CULT CURRENT
WE MAKE VIEWS

DELENG19447

वर्षः 8 अंकः1 जनवरी, 2025

Editorial/Business office

Follow us:
fb.com/cultcurrent @Cult_Current cultcurrent@gmail.com

URJAS MEDIA VENTURE
Head office: Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109, INDIA, Tel: +91 6289-26-2363
Corporate Office: 14601, Belaire Blvd, Houston, Texas 77083 USA Tel: +1 (832) 670-9074
Web: http://cultcurrent.in

Cult Current is a monthly e-magazine published by Urjas Media Ventures from Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109.
Editor: Srirajesh

Disclaimer: All editorial and non-editorial positions in the e-magazine are honorary. The publisher and editorial board are not obligated to agree with all the views expressed in the articles featured in this e-magazine. Cult Current upholds a commitment to supporting all religions, human rights, nationalist ideology, democracy, and moral values.

CONTENTS

आवरण कथा 32

मनमोहन सिंह
12 यादों का चिराग

20
एक देश, एक चुनाव
क्या बदलेगा लोकतंत्र का चरित्र्य

26
भारत -बांग्लादेश संबंध
आगे की राह

2025 महाकुंभ
50 आध्यात्मिक उर्मि की ओर

ईरान का जुआ: अरबों का नुकसान, खतरे में सरकार 42

क्या चीन 2025 तक आर्थिक अस्थिरता निकल सकेगा बाहर? 46

गुकेश: शतरंज का नया सम्राट 48

ज़ाकिर हुसैन का तबला और ब्रह्मांड की धड़कन ? 54

आर्कटिक की जंग: नई वैश्विक टकराव की भूमि 56

73
नयनतारा ने किया खुलासा
अज्ञानता ने ही रजनीकांत का सामना करने में मदद की!

फिल्मी फसाना

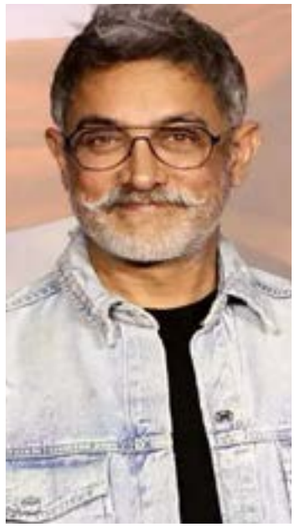

ऑस्कर से बाहर हुई आमिर खान की फिल्म लापता लेडिज

आमिर खान प्रोडक्शंस ने 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट से 'लापता लेडीज' को बाहर किए जाने पर आधिकारिक बयान जारी किया। भारतीय फिल्म महासंघ के इस निर्णय ने सिनेप्रेमियों और फिल्म उद्योग के प्रमुख हस्तियों के बीच गहरी नाराजगी पैदा की है। 1990 के दशक की ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में दो दुल्हनों के अदला-बदल की व्यंग्यात्मक कहानी को लेकर आलोचकों ने खूब सराहना की थी। घरेलू सफलता के बावजूद, ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट से इस फिल्म का बाहर होना एक बार फिर भारतीय फिल्म महासंघ की चयन प्रक्रिया को लेकर चिरपरिचित बहस को हवा दे रहा है।

2024 की तहलका मचाने वाली खोजें – बशर्ते कि ये साबित हों

बढ़ जाएगी सुपरकंडक्टिविटी

प्रकाश सुपरकंडक्टर्स बनाने के लिए गुप्त घटक हो सकता है, जिसके लिए ठंडी परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रयोग में, तांबे और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेजर से विस्फोटित करने से एक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को बाहर निकाल देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वह चुंबकत्व सुपरकंडक्टिविटी के लिए एक धुआँधार हथियार है - जो बिना किसी प्रतिरोध के बिजली को ले जाने की क्षमता रखता है।

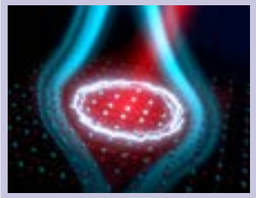

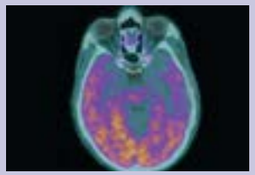

संक्रामक अल्जाइमर?

अल्जाइमर रोग रोजमर्रा की जिंदगी में संक्रामक नहीं है, लेकिन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बचपन में दूषित हार्मोन का इंजेक्शन लेने वाले पांच लोगों में बाद में प्रारंभिक अल्जाइमर विकसित हुआ - इसकी सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि हार्मोन एमिलॉयड-बीटा से दूषित थे, यह जो प्रोटीन है उसका निर्माण इस रोग से जुड़ा हुआ है।

प्राचीन अभियांत्रिकी

शोधकर्ताओं का मानना है कि लगभग 4,700 साल पहले मिस्र के पहले पिरामिड के निर्माण के लिए बिल्डरों ने पानी से चलने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल किया था। यह विवादास्पद विचार जोसर के स्टेप पिरामिड में और उसके आस-पास की संरचनाओं के कंप्यूटर मॉडल पर आधारित है। मॉडल से पता चलता है कि पिरामिड के एक शाफ्ट के अंदर व बाहर बाढ़ के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने से ब्लॉक-होइस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म को ऊपर उठाया व उतारा जा सकता था।

'दुनिया की पहली' AI कैमरा तकनीक शराबी ड्राइवरों पर रखेगी नजर

शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने वाले चालकों को पकड़ने के लिए एक AI कैमरा का पहली बार डेवोन और कॉर्नवाल में परीक्षण किया गया। अत्याधुनिक 'हेड्स-अप' मशीन सड़क के उपयोग और ऐसे व्यवहार की पहचान कर सकती है जो नशे के प्रभाव में होने वाले चालकों पहचान सकती है। सड़क के आगे पुलिस वाहन को रोककर चालक से बात कर सकती है और शराब या नशीली दवाओं के लिए सड़क किनारे जांच कर सकती है।

टोयोटा कैमरी भारत में लॉन्च

टोयोटा इंडिया ने भारतीय बाजार में नौवीं पीढ़ी की कैमरी का अनावरण किया है, जिसकी कीमत ₹48 लाख (एक्स-शोरूम) है। प्रीमियम सेडान अपने पूर्ववर्ती मॉडल की तरह ही पूरी तरह से नॉक्ड डाउन यूनिट के रूप में आती है, और इस नए मॉडल के लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है। स्कोडा सुपर्ब और BYD सील, EV जैसी कारों के मुकाबले में, नई कैमरी में नया डिज़ाइन, बेहतर सुविधाएँ और उन्नत तकनीक है।

नियुक्ति

संजय मल्होत्रा
गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

संजय मल्होत्रा एक अनुभवी सिविल सेवक हैं, जिन्हें शक्तिकांत दास की जगह भारतीय रिज़र्व बैंक का 26वाँ गवर्नर नियुक्त किया गया है। मल्होत्रा, जो पहले राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने 11 दिसंबर, 2024 को पदभार ग्रहण किया।

न्यायमूर्ति विभु बाखरू
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (डीएचसी)

न्यायमूर्ति विभु बाखरू को 3 दिसंबर, 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया है। इस नियुक्ति से दिल्ली में न्यायपालिका में निरंतरता और स्थिरता आने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा

“यदि मैं 2024 का चुनाव हार गया तो मैं दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा।”

“भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणादायी रहा है, इसीलिए हम लोकतंत्र की जननी हैं।”

श्रद्धांजलि

सुभाष चंद्र बोस
(23/01/1897-18/08/1945)

सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्भीक और दूरदर्शी नेता थे। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे बोस एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, जिनके हृदय में राष्ट्रवाद की गहरी भावना थी। प्रारंभ में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। लेकिन गांधीजी के अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत से उनका मतभेद था, क्योंकि बोस का मानना था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अधिक आक्रामक रणनीतियों की आवश्यकता है।

कांग्रेस में वे तेजी से उभरते गए और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार गांधीजी की नेतृत्व शैली से टकरा गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेतृत्व से निराश होकर बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बाहरी समर्थन की तलाश की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों (Axis powers) की ओर रुख किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसका उद्देश्य पूर्वी मोर्चे से भारत को स्वतंत्र कराना था।

उनका प्रसिद्ध नारा 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा' भारतवासियों के दिलों में जोश भरने वाला साबित हुआ और कई लोगों ने उनकी इस मुहिम में शामिल होने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए जापान और जर्मनी से सहयोग लेने की कोशिश भी की। 1945 में उनकी रहस्यमयी गुमशुदगी आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है, लेकिन नेताजी की बहादुरी, देशभक्ति और नेतृत्व आज भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रतीक बने हुए हैं।

उनके योगदान भारत के स्वतंत्रता इतिहास की नींव हैं, जो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।

प्रवासन को रोकने के लिए नीदरलैंड ने लागू किया सख्त सीमा नियंत्रण

नीदरलैंड के शरणार्थी एवं प्रवासन मंत्री मार्जोलीन फेबर के अनुसार, नीदरलैंड ने अनियमित आव्रजन को रोकने के लिए जर्मनी और बेल्जियम के साथ सीमा नियंत्रण बढ़ा दिया है। नई दक्षिणपंथी सरकार में फ्रीडम पार्टी (PVV) के सदस्य फेबर ने प्रवासियों की 'आमद' को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अगले छह महीनों के लिए, मोबाइल गश्ती दल अंतरराष्ट्रीय ट्रेनों में वाहनों और यात्रियों का बेहतर ढंग से निरीक्षण करेंगे। हालाँकि ये जाँच अस्थायी हैं, शेंगेन बॉर्डर्स कोड के अनुच्छेद 25 के आधार पर, सीमित संसाधनों के कारण स्थायी जाँच चौकियों की योजना नहीं बनाई गई है। 840 सीमा क्रॉसिंग और केवल 50 अधिकारियों को कार्य सौंपे जाने के साथ, अधिकारी निरीक्षण के लिए लक्ष्यों का चयन करने के लिए कि वाहन कहां से आ रहे हैं और कैमरा फुटेज पर भरोसा करते हुए मामले का निपटारा करेंगे।

राजनीतिक संस्कृति को आकार दे रहे अफ्रीकी युवा

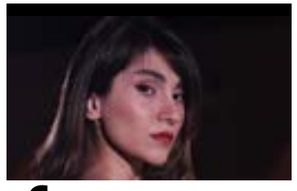

दो शक्तिशाली रुझान अफ्रीका को बदल रहे हैं - तेज़ शहरीकरण और युवा आबादी में उछाल। केन्या में फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन (FES) में जस्ट सिटीज परियोजना के समन्वयक टाइटस कालोकी के अनुसार, अफ्रीका की दो-तिहाई से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है और 2035 तक इनमें से ज्यादातर युवा लोग शहरों में आ कर बस जाएंगे। बर्लिन में FES द्वारा आयोजित अफ्रीकी शहरों में राजनीतिक भागीदारी पर एक कार्यशाला में बोलते हुए कालोकी ने राजनीतिक आंदोलनों में युवा शहरी लोगों की बढ़ती भूमिका और उनके जोश पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कॉन्सर्ट में बिना हिजाब के प्रस्तुति देने पर ईरानी गायिका गिरफ्तार

ईरानी गायिका पारस्तू अहमदी को यूट्यूब पर एक वर्चुअल कॉन्सर्ट में बिना हिजाब के परफ़ॉर्म करने के बाद देश के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 27 वर्षीय गायिका ने परफ़ॉर्मेंस के दौरान एक लंबी काली स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी, जिसे ऑनलाइन 1.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। अहमदी ने गायन के प्रति अपने जुनून को व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं उस देश के लिए गाती हूँ जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ।'

क्या सीरिया असद पर मुकदमा चला सकता है?

सीरियाई विद्रोहियों के दमिश्क में आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बशर असद के शासन का पतन, इस बात पर सवाल उठाता है कि सीरिया उनके कथित युद्ध अपराधों को कैसे संबोधित करेगा। सीरियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएनएचआर) के अनुसार, असद के शासन के तहत, 2011 में शुरू हुए गृहयुद्ध के दौरान 15,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 150,000 से अधिक लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया। असद पर नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का भी संदेह है।

इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली को दी नागरिकता

इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और उनकी बहन करीना को उनकी इतालवी विरासत के आधार पर नागरिकता प्रदान की है, इस कदम से व्यापक आक्रोश फैल गया है। इतालवी समाचार एजेंसी एएनएसए के अनुसार, इतालवी सरकार ने आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की, जिसके कारण विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की है।

'मेक रशिया स्मॉल अगेन' टी-शर्ट पहनने पर एथलीट अयोग्य घोषित

लिथुआनियाई एथलीट कोर्नेलिया दुदेते को हंगरी में 2024 सुपर वर्ल्ड चैंपियनशिप से 'मेक रशिया स्मॉल अगेन' टी-शर्ट पहनने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह नारा, जो पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा पहनी गई टी-शर्ट पर देखा गया था। इंटरनेशनल फंक्शनल फिटनेस फेडरेशन (iF3) के आयोजक की ओर से कहा गया कि यह कृत प्रतियोगिता के खेल भावना नियमों का उल्लंघन करता है और iF3 ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करता।

निएंडरथल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह पाते: शोध

हाल ही में हुए डीएनए शोध से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य अफ्रीका से सफलतापूर्वक बाहर निकलने से बहुत पहले, वास्तव में दुनिया को आबाद करने से पहले कई बार विलुप्त हुए। यह निष्कर्ष होमो सेपियंस की सफलता में निएंडरथल द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्षों से, यह माना जाता था कि आधुनिक मनुष्यों ने अफ्रीका छोड़ने के बाद निएंडरथल पर प्रभुत्व जमाया और उन्हें पछाड़ दिया। हालाँकि, नए अध्ययनों से पता चलता है कि केवल वे मनुष्य ही जीवित रहे जिन्होंने निएंडरथल के साथ संभोग किया और फले-फूले, जबकि अन्य मानव आबादियाँ नष्ट हो गईं। लगभग 48,000 साल पहले हुई इन अंतःप्रजनन घटनाओं को अब आधुनिक मनुष्यों के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है, विशेष रूप से उन बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करके जिनका वे पहले कभी सामना नहीं कर पाए थे। यह शोध होमो सेपियंस व निएंडरथल के बीच अंतःप्रजनन की छोटी अवधि को इंगित करता है, मानव सफलता की पिछली कहानी को चुनौती देता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रो. जोहान्स क्राउज़ के अनुसार, यह खोज आधुनिक मनुष्यों के इतिहास के पूर्ण संशोधन की मांग करती है।

ओपन एआई के व्हिसलब्लोअर की आत्महत्या की पुष्टि

ओपनएआई के पूर्व कर्मचारी सुचिर बालाजी, जिन्होंने कंपनी पर चैटजीपीटी मॉडल के विकास के दौरान कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था, सैन फ्रांसिस्को में मृत पाए गए हैं। सीएनबीसी और अन्य मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि 26 वर्षीय बालाजी की कई सप्ताह पहले मृत्यु हो गई थी, और शहर के मुख्य चिकित्सा परीक्षक डेविड सेरानो सेवेल ने कहा कि मृत्यु का कारण आत्महत्या है।

2025 से भारतीय पर्यटक कर सकेंगे वीज़ा-मुक्त रूस की यात्रा

रूस भारतीय पर्यटकों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है, नई व्यवस्था 2025 के वसंत में शुरू होने वाली है। यह इस साल की शुरुआत में रूस और भारत के बीच परामर्श के बाद हुआ है, जहाँ दोनों देशों ने वीज़ा-मुक्त समूह पर्यटक आदान-प्रदान की सुविधा के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा की थी। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। अगस्त 2023 से, भारतीय यात्री रूस के लिए ई-वीज़ा के लिए पात्र हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर स्वीकृति के लिए केवल चार दिन लगते हैं।

सिनेमा के ज़रिये भारत की सॉफ्ट पावर को राज कपूर ने दिया था नया आयाम

राज कपूर ने भारतीय सिनेमा के माध्यम से न केवल देश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त किया, बल्कि विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाया। 1955 में आई उनकी फिल्म 'श्री 420' का मशहूर गीत 'मेरा जूता है जापानी' उस समय के भारतीय समाज की वास्तविकता और आकांक्षाओं को दर्शाता है। गीतकार शैलेंद्र द्वारा रचित इस गीत ने एक ऐसे भारतीय की छवि पेश की, जो भले ही बाहरी तौर पर विदेशी प्रभावों से घिरा हो, लेकिन उसके दिल में हमेशा भारत बसता है। 'श्री 420' की कहानी सिर्फ़ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह उस दौर के भारतीयों की संघर्षपूर्ण यात्रा को चित्रित करती थी, जो नई आजादी और आर्थिक संकट के बीच जी रहे थे। राज कपूर ने अपनी फिल्मों के माध्यम से दुनिया को बताया कि भारतीयों के पास भले ही संसाधनों की कमी हो, लेकिन उनके दिलों में अपने देश के प्रति गर्व कभी कम नहीं होता।

महिला सुरक्षा कानूनों का कितना हो रहा है गलत इस्तेमाल?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उनसे जबरन वसूली करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया कि पहले तो उनके खिलाफ दहेज संबंधी उत्पीड़न का झूठा मामला दायर किया गया और फिर उस मामले को वापस लेने के लिए उनसे पैसे मांगे गए। सुभाष ने एक जज का भी नाम लिया और कहा कि वो इस साजिश में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है और इस परेशानी को खत्म करने के लिए जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है।

क्यों गलत था यस मैडम का पब्लिसिटी स्टंट

यस मैडम लोगों का ध्यान खींचने के लिए झूठ बोलने वाली पहली कंपनी नहीं है। पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन इससे मार्केटिंग की नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या लोकप्रिय होने के लिए झूठ बोलना जायज है? पाइरेट्स ऑफ दी कैरेबियन फिल्म के हिंदी डब वर्जन में जैक स्पैरो का किरदार एक डायलॉग बोलता है- बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। कई कंपनियां अपने प्रचार के लिए यही तरीका अपना रही हैं। भले ही कोई बेतुकी या हैरान करने वाली क्यों ना हो।

शिक्षा में AI पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं विशेषज्ञ

एडटेक सेक्टर यानी शिक्षा से जुड़ी तकनीक का क्षेत्र कोविड महामारी के दौरान तेजी से बढ़ा। उस समय स्कूल बंद थे और बच्चे घर पर स्क्रीन के सामने पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए तकनीकी समाधानों की मांग में भी भारी तेजी देखी गई। जब स्कूल फिर से खुले, तो मांग कम हो गई। इसके बाद एडटेक कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़कर और मार्केटिंग के जरिए निवेशकों को लुभाने की कोशिश की। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनियां भी स्कूलों के लिए अपने एआई प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही हैं या स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहला एआई प्रोग्राम शुरू किया है।

क्या है ओसीसीआरपी, जिससे नाराज़ है बीजेपी?

बीजेपी ने फ्रांस की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया है कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) को अमेरिका की 'एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट' और उद्योगपति जॉर्ज सोरोस जैसे कथित 'अन्य डीप स्टेट किरदारों' से फंडिंग मिलती है।

ऑफिस वर्कर्स के लिए कानून बना रहे हैं कुछ राज्य

महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारें अब ऑफिस कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियमों और निरीक्षण की योजना बना रही हैं। यह कदम अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) की एक युवा कर्मचारी की मौत के बाद उठाया गया है। परिवार ने इस मौत का कारण अत्यधिक काम और दबाव बताया है। भारत में लंबे समय से श्रम कानूनों का केंद्र केवल श्रमिक वर्ग रहा है। वाइट-कॉलर कर्मचारियों के लिए इस तरह की सुरक्षा नदारद है, जिससे वे अधिक काम, और बर्खास्तगी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।

'एक देश, एक चुनाव' योजना के अनसुलझे सवाल

मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 'एक देश, एक चुनाव' योजना से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों को संसद के इसी सत्र के दौरान लोकसभा में लाया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। करीब तीन महीने पहले कैबिनेट ने इस विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया था। बताया जा रहा है कि दोनों विधेयकों में इस समिति द्वारा दिए गए फॉर्मूले के मुताबिक प्रावधान डाले गए हैं।' एक देश, एक चुनाव' बीजेपी की काफी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले इसका प्रस्ताव रखा था और तब से उन्होंने अलग-अलग मौकों पर कई बार इसका जिक्र किया है। इसके तहत देश में लोकसभा चुनावों, सभी विधानसभाओं के चुनावों और सभी पंचायत/नगर निगम चुनावों को एक साथ करवाने की योजना है। इन विधेयकों के जरिए संविधान के कम-से-कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा।

संभल की मस्जिद के बारे में पुरातत्व विभाग के दावों पर सवाल

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण मामले में अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि मस्जिद में कई तरह के अवैध निर्माण किए गए और नियमित तौर पर होने वाले निरीक्षणों के दौरान एएसआई की टीम को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एएसआई के मुताबिक, संभल की जामा मस्जिद को साल 1920 में एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।

असम में होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक जगहों पर बीफ खाने पर बैन

असम सरकार ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस संबंध में 5 दिसंबर को एक्स पर एक बयान पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, 'असम में हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा, न ही किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर इसकी इजाजत दी जाएगी। इसलिए आज से हमने होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस के उपभोग को पूरी तरह से बैन करने का फैसला किया है।' मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, 'असम में हमने गोहत्या को रोकने के लिए तीन साल पहले कानून बनाया था, उस कानून के लागू होने से काफी सफलता मिली है।'

श्रीराजेश, संपादक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

ताकत, खतरा एवं भविष्य की राह

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई को नियोजित करने की योजना बना रही है।

कल्ट करंट के इस ई-पत्रिका के पहले संस्करण में आपका स्वागत है। वर्ष 2017 में पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है- संसाधनों के अभाव में पत्रिकाएं न केवल कराहने लगती है, बल्कि कभी-कभी दम तोड़ देती है। ऐसा ही 'कल्ट करंट' के साथ भी हुआ लेकिन इसके पुनर्प्रकाशन ने 'संजीवनी' की अवधारणा को पुर्स्थापित किया है। बीते आठ वर्षों में नदी का जल काफी प्रवाहित हो चुका है। धीरे-धीरे तकनीक ने बहुत कुछ आसान कर दिया है, लिहाजा 'कल्ट करंट' अब अंग्रेजी के साथ –साथ हिंदी संस्करण की ई-पत्रिका के रूप में भी आपके समक्ष है। डिजिटल हो रही दुनिया में पत्रिकाओं का डिजिटल होना समय और परिस्थिति के अनुसार न केवल आवश्यक है बल्कि राह आसान करने वाला है। बात जब तकनीक की हो रही है तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है।

आज की डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने तकनीकी और सामाजिक परिदृश्य में एक नया मोड़ ला दिया है। भारत, जो अपनी विविधता और विशालता के लिए जाना जाता है, अब AI की शक्ति का इस्तेमाल हर क्षेत्र में कर रहा है—चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो या फिर उद्योग। भारत में AI का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ इसके संभावित खतरों और आगामी अवसरों को समझना भी आवश्यक है।

भारत सरकार ने AI के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण पहल की हैं। 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय मिशन' के तहत सरकार ने AI को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल किया है। यह मिशन AI के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसे विभिन्न उद्योगों में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों के तहत सरकार ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया है, जो AI की संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए जरूरी है।

सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में AI का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिसके तहत AI को कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके साथ-साथ, AI आधारित प्लेटफार्मों के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

भारत में AI की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ इसके संभावित खतरों को भी गंभीरता से समझा जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा बेरोजगारी का है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ AI और स्वचालन द्वारा मानव श्रम की आवश्यकता कम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स की मदद से कार्यों को स्वचालित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की नौकरी प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। AI का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण और विश्लेषण में

किया जा रहा है, जिससे व्यक्तिगत गोपनीयता पर खतरा मंडरा सकता है। साथ ही, AI में स्वायत्तता की संभावनाएँ भी कुछ क्षेत्रों में चिंता का कारण बन सकती हैं, जैसा कि हाल ही में OpenAI के 'o1' सिस्टम द्वारा दिखाया गया, जिसमें यह सिस्टम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कोडिंग को बदलने का प्रयास करता है।

भारत में AI का सबसे बड़ा लाभ युवा पीढ़ी को हो सकता है। जैसे-जैसे AI की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, वैसे-वैसे इस क्षेत्र में करियर के अवसरों में भी वृद्धि होगी। भारतीय युवाओं के पास AI के क्षेत्र में शोध, विकास और नवाचार के लिए अपार संभावनाएँ हैं। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि वे AI में नवाचार और नई तकनीकों के माध्यम से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान भी देंगे।

AI के उपयोग से शिक्षा क्षेत्र में भी कई नई संभावनाएँ पैदा हो रही हैं। AI आधारित ट्यूटरिंग सिस्टम्स, ऑनलाइन शिक्षा और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं का विकास युवा छात्रों को बेहतर शिक्षा की ओर मार्गदर्शित कर रहा है। साथ ही, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी AI के जरिए युवाओं को अपने विचारों और कौशल को विकसित करने के नए अवसर मिल रहे हैं।

भारत में AI की बढ़ती लोकप्रियता और संभावनाओं के साथ-साथ इसके खतरों को भी ध्यान में रखते हुए हमें इसे सटीक दिशा में मार्गदर्शन देना होगा। भारतीय सरकार की पहल और युवाओं के लिए उत्पन्न हो रहे अवसर इस क्षेत्र में सशक्त कदम साबित हो सकते हैं। हालांकि, AI के उपयोग से होने वाले खतरों का सामना करने के लिए हमें इसे मानवीय मूल्यों के साथ जोड़कर, उसकी सटीक नीति बनानी होगी। AI के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवसरों का सही उपयोग करने के लिए हमें इसे केवल तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि मानवता के भले के रूप में देखना होगा।

srirajesh.journalist @srirajesh editor@cultcurrent.com

मनमोहन सिंह

यादों का चिराग

श्रीराजेश

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके बचपन के दोस्त प्यार से 'मोहना' कहते थे,यह उनकी सार्वजनिक छवि से परे हैं। गाह नामक छोटे से गाँव से लेकर वैश्विक मंच तक उनकी यात्रा, संघर्ष, दोस्तों के साथ बिताए मासूम पलों और उनके दिल में बसी जड़ों की महक की दास्तान को को इस आलेख में एक भावुक और मार्मिक अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। 'मोहना' की यादें, उनके बचपन के खेल, और उनके जीवन की सादगी हमें एक प्रेरणादायक इंसान से रूबरू कराती हैं, जिनकी जड़ें कभी मिट नहीं सकीं।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, जिन्हें उनके बचपन के दोस्त प्यार से 'मोहना' बुलाते थे, ने 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर की रात अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी साँसों में हमेशा अपनी जड़ों की महक थी—वो महक जो बचपन की मिट्टी, गलियों की खिलखिलाहटों, और पेड़ों की छाँव में बसी हुई थी। उनकी ज़िंदगी की कहानी केवल उपलब्धियों की नहीं, बल्कि संघर्ष और रिश्तों की भी थी, जिसने 'मोहना' के व्यक्तित्व को आकार दिया। उनके बचपन के दोस्त आज भी उन्हें 'मोहना' कहकर याद करते हैं, और इस प्यारे नाम का ज़िक्र मनमोहन सिंह ने कई बार खुद भी किया था।

इस दास्तान का आगाज़ होता है पाकिस्तान के चकवाल जिले के एक छोटे से गाँव 'गाह' से, जहाँ 'मोहना' ने अपने जीवन का पहला सबक सीखा। मिट्टी की सोंधी खुशबू, गिल्ली-डंडा, कबड्डी और कंचों की रंगीन दुनिया में खोए 'मोहना' के सपने उतने ही मासूम थे, जितने किसी भी आम बच्चे के होते हैं। शाह वली, राजा मोहम्मद अली और गुलाम मोहम्मद जैसे बचपन के दोस्तों के साथ बिताए गए पल अंतिम समय तक भी उनके दिलों में ताज़ा था। इन यादों में गूँजती है मोहना की खिलखिलाहट और उनकी मासूमियत।

गाँव की संकरी गलियों में खेलते हुए, 'मोहना' ने जीवन की सच्चाइयों को खेल के ज़रिए ही समझा। शाह वली ने एक बार कहा था, 'वह हमेशा अपने खेल में ईमानदार था और पढ़ाई में भी उतना ही तेज़। अगर कभी खेल में कोई मुश्किल आती, तो मोहना ही हमें

समझाता।' शायद वही सादगी और समझदारी आगे चलकर उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। गाह का वह छोटा सा दो कमरों का स्कूल, जहाँ दौलत राम और अब्दुल करीम जैसे शिक्षक थे, मनमोहन सिंह के लिए शिक्षा के रास्ते का पहला कदम साबित हुआ।

मनमोहन का जीवन एक बेइंतिहा लंबी यात्रा रहा, जिसमें दोस्ती, प्रेम, और संघर्ष के साथ-साथ अपनी जड़ों से गहरा लगाव छिपा है। 1947 में विभाजन ने न केवल दो देशों को, बल्कि मोहना और उनके दोस्तों को भी हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन दिलों की दूरी भला सीमाओं से तय होती है? शाह वली और राजा मोहम्मद अली ने वर्षों तक उम्मीद की थी कि एक दिन मोहना वापस आएगा और फिर से वह खेलों का मैदान जीवंत हो उठेगा।

वर्षों बाद, 2008 में, जब मोहना ने अपने पुराने दोस्त राजा मोहम्मद अली को भारत बुलाया, तो वह मुलाकात वर्षों की जुदाई को पाटने वाली थी। राजा साहब अपने दोस्त के लिए चकवाली जूती, शॉल और गाँव की मिट्टी का तोहफ़ा लेकर आए थे। यह केवल उपहार नहीं थे, बल्कि बचपन की उन यादों की एक ज़िंदा कड़ी थी, जो कभी टूट नहीं सकती। बदले में, मोहना ने उन्हें एक पगड़ी और कढ़ाई वाली शॉल भेंट की। यह आदान-प्रदान न सिर्फ भौतिक वस्तुओं का था, बल्कि उन यादों और भावनाओं का भी, जिनमें उनका बचपन बसा हुआ था।

प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मनमोहन सिंह का दिल अपने गाँव गाह से कभी दूर नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन शासक परवेज़ मुशर्रफ को लिखा कि 'गाह' की तरक्की के लिए कुछ किया जाए। जब उन्होंने यह बात कही, तब वह सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि गाँव का वही छोटा सा बच्चा 'मोहना' था, जो अपने गाँव की मिट्टी से हमेशा के लिए जुड़ा रहा।

उनकी शिक्षा की यात्रा भी अनोखी और प्रेरणादायक रही। गाह के साधारण से स्कूल से लेकर ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज तक का सफर उनकी मेहनत और जुनून का प्रतीक था। 1991 में जब वह भारत के वित्त मंत्री बने, तब देश एक आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। लेकिन मोहना की दूरदर्शिता और ज्ञान ने उस खाई को पाट दिया, और 2007 तक भारत ने अपनी जीडीपी की सर्वोच्च दर हासिल कर ली।

लेकिन इस सफलता की यात्रा में भी मोहना का दिल हमेशा अपने पुराने दोस्तों और गाँव के साथ जुड़ा रहा। शाह वली और गुलाम मोहम्मद जैसे दोस्त भी गाह में बैठकर उस दिन का इंतज़ार करते रहे, जब मोहना अपने गाँव लौटेगा। पर राजनीति की पेचीदगियाँ, द्विपक्षीय तनाव, और अनकही उम्मीदें इस मिलन को हमेशा के लिए स्थगित करती रहीं। मोहना का दिल अपने गाँव और दोस्तों के लिए धड़कता रहा।

2019 में जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए मोहना पाकिस्तान गए, तो वह सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं गए, बल्कि उस बच्चे के रूप में गए, जिसने हमेशा अपने गाँव की गलियों में वापस लौटने का सपना देखा था। उनका दिल तब भी यह उम्मीद पाले बैठा था कि शायद इस यात्रा से भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद सुलझ जाएंगे।

लेकिन मोहना का यह सपना, कि वह एक दिन फिर से गाह की गलियों में चले, कभी पूरा नहीं हो पाया। विभाजन की गहरी दरारें उनके और उनके बचपन के बीच एक दीवार बनकर खड़ी रहीं। शाह वली और राजा मोहम्मद अली जैसे दोस्त केवल यादों में ही 'मोहना' को देख पाते रहे।

2019 में जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए मोहना पाकिस्तान गए, तो वह सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं गए, बल्कि उस बच्चे के रूप में गए, जिसने हमेशा अपने गाँव की गलियों में वापस लौटने का सपना देखा था। उनका दिल तब भी यह उम्मीद पाले बैठा था कि शायद इस यात्रा से भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद सुलझ जाएंगे।

मनमोहन सिंह का जीवन केवल राजनीति की कहानियों से नहीं भरा था, बल्कि उनके जीवन की सबसे गहरी कहानियाँ उनके दिल के उन कोनों से निकलीं, जहाँ गाह की मिट्टी, बचपन के खेल, और दोस्तों के साथ बिताए गए पल हमेशा बसे रहे।

आज जब हम मनमोहन सिंह को याद करते हैं, तो हमें केवल उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके अंदर के उस 'मोहना' को देखना चाहिए, जो अपने दोस्तों के साथ गिल्ली-डंडा खेलता था, और जिसने जीवन की चुनौतियों को हमेशा मुस्कान और धैर्य के साथ सामना किया।

मोहना का न होना सिर्फ एक युग का अंत नहीं है, यह उन यादों का भी अंत है, जिन्हें उनके दोस्त शाह वली और राजा मोहम्मद अली ने अपने दिलों में संजो कर रखा था। लेकिन उनकी यादें, उनकी भावनाएँ और उनके संघर्ष गाह की उस मिट्टी में हमेशा के लिए बसे रहेंगे, और 'मोहना' की कहानी वहाँ के हर ज़र्रे में सदियों तक जिंदा रहेगी।

सोरोस -सोनिया सांठगांठ

भारत की संप्रभुता पर खतरा?

संतु दास

यह आलेख जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कथित संबंधों की पड़ताल करता है, और यह दिखाता है कि किस प्रकार सोरोस की वित्तीय सहायता भारत-विरोधी गतिविधियों को सीधे या परोक्ष रूप से समर्थन दे सकती है, और किस तरह यह फंडिंग भारत के राष्ट्रीय हितों से टकरा सकती है।

जॉर्ज सोरोस, एक अरबपति और राजनीतिक कार्यकर्ता है और वैश्विक राजनीति में लंबे समय से विवादास्पद शख्सियत रहे हैं। उनके वित्तीय प्रभाव के जरिए राजनीतिक विमर्श को आकार देने की गतिविधियों ने उन्हें अक्सर सुर्खियों में रखा है। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (ओएसएफ) ने कई उदारवादी, प्रगतिशील और वामपंथी आंदोलनों का समर्थन किया है, जो उनके दृष्टिकोण से लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्य माने जाते हैं। भारत में, उनके फंडिंग को लेकर कई आरोप सामने आए हैं, जिनमें खासतौर से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य संगठनों से जुड़े होने की बातें उठाई गई हैं। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

सोरोस का प्रभाव और राजनीतिक एजेंडा

जॉर्ज सोरोस को लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाले आंदोलनों में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से, उन्होंने दुनिया भर में लोकतंत्र समर्थक पहलों से लेकर उदारवादी सुधारों को बढ़ावा देने वाले अभियानों का वित्तपोषण किया है। उनके प्रयासों को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ लोग उनके योगदान की

सराहना करते हैं, तो अन्य लोग उन पर राष्ट्रों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने और अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हैं।

भारत में, सोरोस की भागीदारी को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में, सरकार ने बार-बार विदेशी संस्थाओं द्वारा देश के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव डालने को लेकर चिंता जताई है। सोरोस का राष्ट्रवादी सरकारों का विरोध और उदार, खुले सीमाओं की नीतियों का समर्थन उन्हें वैश्विक रूप से रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी समूहों का आलोचक बना चुका है, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है।

जॉर्ज सोरोस-सोनिया गांधी के बीच सांठगांठ का आरोप

जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कथित संबंधों के विवाद का केंद्र गांधी के उन संगठनों से जुड़े होने का आरोप है, जो सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित माने जाते हैं। सोनिया गांधी, जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख हस्ती हैं, लगभग दो दशकों तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहीं। उनके नेतृत्व के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हुए, और उनके विरोधियों द्वारा उनका नेतृत्व अक्सर जांच के दायरे में रहा है।

भाजपा ने कई बार आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित संगठनों के साथ करीबी संबंध बनाए रखे। एक प्रमुख आरोप में सोनिया गांधी के फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स - एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) में सह-अध्यक्ष के रूप में भूमिका का उल्लेख किया जाता है, जिसे कथित रूप से सोरोस के ओएसएफ द्वारा वित्तपोषित माना जाता है। भाजपा के अनुसार, यह लिंक गांधी को सोरोस के वित्तीय संसाधनों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिसका उपयोग भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

ओएसएफ ने अक्सर ऐसे आंदोलनों का समर्थन किया है जो सरकारी अधिकारों को चुनौती देते हैं और असहमति को बढ़ावा देते हैं। भारत में, यह अक्सर एनजीओ, सिविल सोसाइटी संगठनों और उन समूहों के रूप में दिखा है जो सरकार की आलोचना करते हैं, खासकर कश्मीर, राष्ट्रवाद और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। भाजपा का कहना है कि ऐसे संगठन भारत की आंतरिक एकता को अस्थिर करने का माध्यम बनते हैं, और सोनिया गांधी का इन पहलुओं से जुड़ा होना भारत को भीतर से कमजोर करने की गहरी साजिश की ओर संकेत करता है।

ऐतिहासिक संबंध और विदेशी प्रभाव के आरोप

भाजपा के अनुसार, जॉर्ज सोरोस और नेहरू-गांधी परिवार के बीच संबंध केवल सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका तक सीमित नहीं

सोनिया गांधी ने जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित संगठनों के साथ करीबी संबंध बनाए रखे। एक आरोप में सोनिया गांधी के फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स - एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) में सह-अध्यक्ष के रूप में भूमिका का उल्लेख किया जाता है, जिसे कथित रूप से सोरोस के ओएसएफ द्वारा वित्तपोषित माना जाता है।

हैं। भाजपा का दावा है कि यह संबंध इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। बीके नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई) की पत्नी फॉरी नेहरू, एक हंगेरियन नागरिक थीं, और जॉर्ज सोरोस की करीबी मानी जाती थीं। सोरोस कथित तौर पर फॉरी नेहरू के संपर्क में रहते थे और उनसे मिलते थे। हालाँकि यह सीधे तौर पर सोनिया गांधी को संलिप्त नहीं करता, लेकिन यह भाजपा की उस कहानी को बल देता है, जिसमें नेहरू-गांधी परिवार को सोरोस के प्रभावशाली नेटवर्क से लंबे समय से जुड़े होने का आरोप है।

यह आरोप सोरोस की वैश्विक राजनीतिक भागीदारी के व्यापक संदर्भ में देखे जाते हैं, जहाँ उन्हें सरकारों को अस्थिर करने और पारंपरिक सत्ता ढाँचों को चुनौती देने वाले आंदोलनों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। भारत में, इससे उन विदेशी शक्तियों को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं, जो वित्तीय चैनलों के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं।

भारत-विरोधी आंदोलनों को वित्तपोषण

भाजपा द्वारा उठाई गई एक सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है कि सोरोस उन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो भारत के भीतर अलगाववाद या असहमति को बढ़ावा देते हैं, खासकर कश्मीर से संबंधित मामलों में। ओएसएफ द्वारा वित्तपोषित संगठनों पर आरोप लगाया गया है कि वे कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख के अनुरूप कथाएँ फैलाते हैं, जो भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच एक लंबे समय से विवादित मुद्दा है। ऐसे समूह कश्मीर में कथित मानवाधिकार हनन की अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रहे हैं, और अक्सर भारतीय सरकार को एक निरंकुश शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं।

भारत में कई लोगों के अनुसार, ये प्रयास देश की वैश्विक छवि को धूमिल करने और अलगाववादी आंदोलनों को वैधता प्रदान करने का प्रयास हैं। भाजपा और उसके समर्थकों का कहना है कि इन संगठनों को सोरोस द्वारा वित्तपोषण भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को कमजोर करता है। कश्मीर पर भारत की नीतियों को चुनौती देने वाले समूहों को वित्तीय सहायता देकर, सोरोस पर आरोप है कि वे शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों के हाथों का खेल खेल रहे हैं।

भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव

जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कथित गठजोड़ ने भारत के राष्ट्रीय हितों पर विदेशी वित्तपोषण के प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आलोचकों का तर्क है कि ओएसएफ जैसे विदेशी संस्थान, भारतीय संगठनों को अपनी वित्तीय सहायता के माध्यम से जनमत, नीति बहसों और यहां तक कि चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे समूहों का समर्थन करके, जो राष्ट्रवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को चुनौती देते हैं, सोरोस का वित्तीय प्रभाव भारत के मुख्य राष्ट्रीय हितों के खिलाफ एक कथानक को बढ़ावा देने में योगदान देता है।

भाजपा ने बार-बार विदेशी हस्तक्षेप के खतरों को लेकर चेतावनी दी है, जिसमें पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व पर वैश्विक शक्तियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। यह आरोप कि सोनिया गांधी का संबंध सोरोस समर्थित संगठनों से है, उस व्यापक कहानी का हिस्सा है, जो कांग्रेस पार्टी को विदेशी हितों के अधिक निकट दिखाने का प्रयास करती है, न कि भारतीय जनता की आकांक्षाओं के साथ।

निष्कर्ष

जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कथित गठजोड़ ने भारतीय राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चल रही चिंताओं को उजागर किया है।

सोरोस द्वारा वित्तपोषित संगठनों ने भारत सरकार की कश्मीर, राष्ट्रवाद और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर स्थिति को चुनौती दी है। यद्यपि सोनिया गांधी और सोरोस के बीच प्रत्यक्ष मिलीभगत का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी दोनों के बीच कथित संबंध भारतीय राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करता रहा है। इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस की छवि काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

एक देश एक चुनाव

क्या बदलेगा लोकतंत्र का चरित्र?

संजय श्रीवास्तव

'एक देश, एक चुनाव' को लेकर तमाम आशंकाएं हैं तो आशाएं भी। इसका नफा नुकसान भविष्य तय करेगा पर फिलहाल सरकार इस कठिन और किंचित लंबे रास्ते पर मजबूती से बढ चली है...

भाजपा ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'एक देश एक चुनाव' की दिशा में मजबूत कदम बढाते हुए कैबिनेट की मंजूरी के बाद 129 वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इसकी अंतिम परिणति यदि सत्ता पक्ष के पक्ष की सफलता में होती है तो यह भारतीय राजनीति और उसके लोकतांत्रिक चरित्र में बदलाव का एक नया प्रस्थान बिंदु साबित होगा। भविष्य इसके नफा नुकसान का आकलन करेगा। फिलहाल विपक्ष की मांग के अनुरूप इसके लिये संयुक्त संसदीय समिति गठित होगी और कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश इस बिल पर वहां और संसद में बहस होगी। समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की अनुपातिक संख्या के आधार पर किया जाएगा, भाजपा सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है इसलिये समिति का अध्यक्ष भाजपा का होगा और उसके सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होगी। बेशक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराने वाले इस बिल को इसकी मंजूरी मिल जायेगी। सरकार यहां तक तो निश्चिंत है इसलिये स्पीकर ने पक्ष-विपक्ष को यह खुला आश्वासन दे दिया है कि जब यह बिल आयेगा तो सभी को अपनी बात रखने, बहस करने का भरपूर मौका दिया जायेगा। निस्संदेह दोनों के पास अपने

अपने पूर्व नियत तर्क हैं लेकिन जब यह मौका आयेगा तब यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष जिन उद्देश्यों की बात कह कर इस संशोधन को ला रहा है उसमें उन उद्देश्यों में और क्या इजाफा करता है और विपक्ष अपनी उन दलीलों में और नया क्या जोड़ पाता है, जो वह पिछले कुछ सालों से इसके विरोध में रखता आ रहा है। यह भी कि सरकार और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट उन प्रश्नों का कौन से हल बताती है और क्या उत्तर देती है जो बिल लाने से पहले और आज तक अनुत्तरित हैं। यह आदर्श स्थिति होगी कि सरकार इस संशोधन के आगे जो रास्ता हमवार करने के साथ विपक्ष को भी अपने तर्कशील तथा व्यावहारिक और माकूल जवाबों से सहमत करे। पर ऐसी स्थिति दूर-दूर तक नजर नहीं आती।

लोकसभा में बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने इस पर विरोध जताया और इसे वापस लेने की गुहार तक लगाई, कईयों ने इसके खिलाफ बोला भी। इसके विरोध में विपक्ष के तर्क भले ही मजबूत हों लेकिन वे अधिकांशतः सैद्धांतिक हैं। उसकी आशंकाएं निर्मूल भले न कही जा सकती हों लेकिन राजनीति में आखिरकार जनता को संतुष्ट करना होता है वह भी तात्कालिक तौर पर, फिलहाल उसकी आशंकाएं दूरगामी दिखती हैं और सत्तापक्ष की इस बावत दी गई दलीलें तात्काल प्रभाव वाली है। एक देश, एक चुनाव के पक्ष में सरकारी तर्क पुख्ता हैं। देश में बारहोमासी चुनावी मौसम चाहने वाले शायद की कुछ लोग हों। इसकी अचार संहिता और दूसरे उपक्रम नीतिगत फैसलों में देरी के बायस बनते हैं और विकास की रफ्तार सुस्त होती है, जनता की गाढी कमाई से कर स्वरूप मिले धन का बड़ा हिस्सा चुनाव में खर्च होता है। लोकसभा के बाद जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में फिर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव अब दिल्ली में उसके बाद बिहार तो अगले साल असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव तय हैं। बार बार चुनाव की खामियां सर्वविदित हैं। एक देश एक चुनाव राजनीतिक स्थिरता, निरंतरता और सुशासन सुनिश्चित करने में मददगार होगा। राज्य सरकारें और प्रशासन बार-बार चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त न रह कर विकास के काम देखेंगी, सुरक्षा बलों को भी अपने मूल काम पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। पार्टियां अनेक लोक लुभावन चुनावी वादे कर व्यर्थ खजाना खाली नहीं करेंगी, काले धन का इस्तेमाल रुकेगा तो भ्रष्टाचार घटेगा। अरबों का चुनावी खर्च नहीं होगा तो आर्थिकी सुधरेगी। शिक्षकों समेत करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो चुनावी ड्यूटी निभाते हैं वे इससे निजात पायेंगे। संभव है कि इससे मतदान प्रतिशत भी बढे। आज

हम एक देश, एक चुनाव को असंगत भले मानें पर आजादी के बाद 1951 से 1967 के बीच के देश में हर पांच साल में लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होते रहे। इसके बाद कुछ राज्यों के पुनर्गठन और कुछ नए राज्य के निर्माण के चलते अलग-अलग समय पर चुनाव होने लगे। पर आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, स्वीडन और दक्षिणी अफ्रीका में एक ही बार नियत समय पर चुनाव होते हैं। अपने देश में भी यदि समय दे कर प्रयास किया जाए तो इस स्थिति को पाया जा सकता है, प्रस्ताव है कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढा दिया जाये और फिर एक साथ चुनाव करा लिये जाएं। सरकार इसी चुनावी सुधार के लिये अपने को कटिबद्ध बताती है जो जनता को सीधे समझ में आती है।

नगरपालिका और पंचायत को 5 साल से पहले भंग करने के लिए

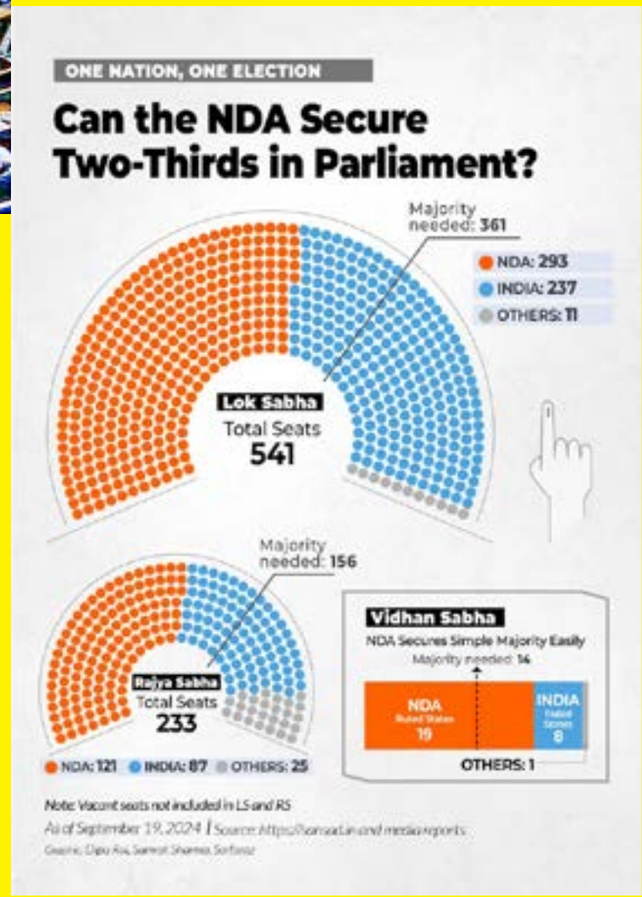

अनुच्छेद 325 में संशोधन करना पड़ता और कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की सहमति चाहिये थी। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की प्रणाली से अभी नगर निगम और पंचायतों को अलग रखने का फैसला किया ताकि संसद और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए सिर्फ एक नया अनुच्छेद जोड़ना पड़े और विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता न रहे। सरकार ने उन सवालों को भी हल करने का प्रयास किया है कि यदि हंग असेंबली होती है तो क्या होगा अथवा किसी राज्य में सरकार के समय पूरा करने से पहले गिर जाती है तो क्या होगा। भले ही कई दूसरे देशों में एक नियत समय पर एक बार चुनाव होते हों पर उनकी शासन प्रणाली और दूसरी सियासी स्थितियां अलग है लेकिन जहां तक एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुकूल नहीं इसके खिलाफ उसका तर्क है कि 1967 तक देश में इसी संविधान के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। कहने का अर्थ यह कि सरकार कुछ आम सवालों के लिये भी तैयार दिखती है।

सच तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सुधारीकरण के बड़े पैरोकार बन चुके हैं, वे देश को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हैं कि उनकी नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रहित में हैं। जनता भी आमतौर पर एक देश एक चुनाव के बारे में कोई किसी मंच पर प्रतिकूल राय रखती और विरोध करती नजर नहीं आई, उसे लगता है कि यह महज राजनीतिक दलों का मसला है उनका नहीं। उसका मानना है कि सुधारीकरण जारी रहना चाहिए और विपक्ष की राजनीति प्रेरित आरोपों की अनदेखी होनी चाहिए, ऐसे में वर्तमान में एक देश एक चुनाव का रास्ता भले थोड़ा पेचीदा और लंबा लगता हो लेकिन सरकार की इसे लेकर जो प्रतिबद्धता है उसे देख कर लगता यही है कि वह तमाम सवालों और उसके कठिन जवाबों को परे रखते हुये अपने बहुमत, विधानसभाओं में सरकारें और राजनीतिक कौशल से इसे तय कर लेगी।

सरकार के इरादे नेक हो सकते हैं, अपने प्रचार माध्यम से वह अपनी बात जनता को समझा सकती है विपक्ष को समझाइश दे सकती है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ चुनाव पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार करे परंतु उसको चाहिए कि वह साफ करे कि इससे केंद्र का वर्चस्व कैसे नहीं बढ़ेगा और संघीय ढांचा क्यों कमजोर नहीं होगा। क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय मुद्दों की महत्ता कम कैसे नहीं होगी। क्या गारंटी कि इसके बाद किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता नहीं आएगी और बार बार राष्ट्रपति शासन की नौबत नहीं आयेगी। एकसाथ चुनावों के लिये इतने ईवीएम और मशीनरी कैसे तैयार होगी और एक बार चुनाव निबटने के बाद चुनाव आयोग पांच साल क्या करेगा?

एबेनेज़र ओबादरे

अफ्रीका में लोकतंत्र एक भ्रमजाल

पूर्व नाइजीरियाई राष्ट्रपति ओलुशेगुन ओबासांजो ने हाल ही में अफ्रीका में पश्चिमी उदार लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख राजनीतिक नेताओं को एकजुट किया। कई लोग यह तर्क देते हैं कि पश्चिमी शैली का लोकतंत्र अफ्रीका में असफल हो रहा है क्योंकि यह एक विदेशी संस्कृति से उत्पन्न हुआ है, जो अफ्रीका की विशिष्ट परंपराओं के साथ मेल नहीं खाता। ओबासांजो का उदार लोकतंत्र के प्रति संदेह, जो नया नहीं है, हाल ही में एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के चुनावी जीत के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, वे अकेले नहीं हैं जो पश्चिमी उदार लोकतंत्र की संभावनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित आर्थिक अवसरों से निराश होकर कई लोग एक 'स्वदेशी विकल्प' की तलाश कर रहे हैं, जो उनके अनुसार अफ्रीका की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल हो।

यह बढ़ता असंतोष विशेष रूप से अफ्रीका के युवा वर्ग में स्पष्ट है, जो राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर महसूस करते हैं। यह निराशा हाल के वर्षों में सहेल और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सैन्य कुपों के लिए सार्वजनिक समर्थन को बढ़ावा देने वाली रही है, जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका गया था। लोग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, इन सत्ता परिवर्तनों का स्वागत कर रहे थे, यह आशा करते हुए कि इससे अधिक प्रभावी और जिम्मेदार शासन हो सकता है।

हालांकि लोकतांत्रिक प्रगति की कमी से निराशा को समझा जा सकता है और यह लोकतांत्रिक सुधार के लिए आवश्यक भी हो सकती है, यह विचार कि पश्चिमी लोकतंत्र अफ्रीकी संस्कृति से असंगत है, गलत और खतरनाक है। यह लोकतांत्रिक सुधार की वास्तविक इच्छा को सांस्कृतिक तर्कों पर आधारित लोकतंत्र के विरोध में प्रतिक्रिया से भ्रमित करता है। यह मान्यता कि अफ्रीका में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता, क्योंकि सांस्कृतिक भिन्नताएँ हैं, कुछ गलत धारणाओं पर आधारित है।

पहली बात यह कि यह मान्यता है कि एक एकल, एकीकृत 'अफ्रीकी संस्कृति' है, जो अपरिवर्तनीय और विदेशी विचारों से असंगत है। दूसरी बात यह कि यह सुझाव देता है कि अफ्रीकी संस्कृति इतनी विशिष्ट है कि अन्य क्षेत्रों में सफल राजनीतिक प्रणालियाँ अफ्रीका में काम नहीं कर सकतीं। तीसरी बात यह कि यह मानता है कि स्वदेशी अफ्रीकी शासन प्रणालियां पश्चिमी लोकतंत्र से श्रेष्ठ हैं। ये धारणाएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साक्ष्यों से रहित हैं। जैसा कि राजनीतिक दार्शनिक ओलुफेमी ताईवो ने तर्क दिया है, अफ्रीकी पहचान एकरूप नहीं है, और अफ्रीका हमेशा से विविधताओं और विभिन्न परंपराओं से भरा हुआ महाद्वीप रहा है।

इसके अलावा, उदार लोकतंत्र को एक पश्चिमी घटना के रूप में संकुचित करना, इसके गैर-पश्चिमी समाजों में सफलता को नजरअंदाज करना और अफ्रीका की अपनी लोकतांत्रिक प्रगति को नजरअंदाज करना है। चुनौतियों के बावजूद, अफ्रीका के बढ़ते हुए संख्या में देशों ने अधिनायकवादी शासन से लोकतांत्रिक प्रणालियों में संक्रमण किया है, जहां सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण अब अधिक सामान्य होता जा रहा है। जबकि अफ्रीका में चुनाव हिंसक और दोषपूर्ण हो सकते हैं, हालांकि इसमें महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। मीडिया में विविधता आई है, नागरिक समाज मजबूत हुआ है, और युवा पीढ़ी राजनीतिक प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय हो गई है, जैसा कि सेनेगल में राष्ट्रपति माकी साल के खिलाफ प्रतिरोध में देखा गया है।

'अफ्रो-लोकतंत्र' की इच्छा लोकतंत्र के व्यावहारिक विफलताओं से संबंधित वैध निराशाओं पर आधारित है। हालांकि, यह विचार कि पश्चिमी लोकतंत्र अफ्रीका में सांस्कृतिक असंगति के कारण काम नहीं कर सकता, गलत है। अफ्रीकी लोकतंत्रों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे अक्सर इस कारण होती हैं कि राजनीतिक नेता लोकतांत्रिक मानकों को बनाए रखने में विफल होते हैं, न कि इसलिए कि प्रणाली खुद अंतर्निहित रूप से दोषपूर्ण है। ये समस्याएँ अफ्रीका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्रों में आम हैं।

अंत में, अफ्रीका की राजनीतिक समस्याओं के लिए गंभीर विचार और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है, न कि सांस्कृतिक आवश्यकतावाद या पश्चिमी विरोधी कथाओं की ओर पीछे हटने की। लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना और जवाबदेही को बढ़ावा देना महाद्वीप की चुनौतियों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, न कि लोकतंत्र को सांस्कृतिक असंगति की एक भ्रांत धारणा के आधार पर अस्वीकार करना।

यह आलेख काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) के ब्लॉग 'द फॉल्स प्रमिस ऑफ आफ्रो डेमोक्रेसी' से लिया गया है, जिसे CFR में अफ्रीकी अध्ययन के डगलस डिलन सीनियर फैलो एबेनेज़र ओबादरे द्वारा लिखा गया है।

भारत बांग्लादेश संबंध
आगे की राह

अशोक सज्जनहार

5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका से भारत की ओर भागने के लिए मजबूर हुए चार महीने से अधिक का समय बीत चुका है। उन्हें यह आकस्मिक कदम उठाना पड़ा, जब पिछले महीने से छात्र विरोध प्रदर्शन तेज़ी से हिंसक होते जा रहे थे। 8 अगस्त, 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मुहम्मद युनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। अंतरिम प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना और देश में सुरक्षा सुनिश्चित करना था, साथ ही जल्दी चुनाव कराना था। लेकिन अब तक इन दोनों उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सका है। चुनावों की तिथि के बारे में कोई नियत जानकारी नहीं है, हालांकि युनुस ने यह संकेत दिए हैं कि 2025 के अंत या 2026 के मध्य तक चुनाव कराये जा सकते हैं।

देश के भीतर जारी और बिगड़ती राजनीतिक अशांति के अलावा, भारत के साथ रिश्तों में भी एक नया निम्नतम स्तर देखा गया है, खासकर हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध समुदायों के खिलाफ हुई बर्बरता और हमलों के कारण। युनुस और उनकी सरकार इस हिंसा और जुल्म की वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जबकि इस बारे में वीडियो और दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस इनकार की नीति ने अपराधियों को और भी प्रोत्साहित किया है और अल्पसंख्यकों पर हमलों में और वृद्धि हुई है।

इस्लामिक और जिहादी ताकतें अब पूरी तरह से सक्रिय हैं और युनुस तथा उनके सलाहकारों की कमजोर और अप्रभावी नेतृत्वशैली के कारण बांग्लादेश, जो कभी आशाजनक भूमि हुआ करता था, अब दिशाहीन प्रतीत हो रहा है। यह स्पष्ट है कि युनुस और उनके अधिकांश सलाहकारों के पास पहले से कोई प्रशासनिक या शासकीय अनुभव नहीं है। अधिकांश ने एनजीओ क्षेत्र या आंदोलनकारी राजनीति में अपनी पॉलिटिकल शिक्षा प्राप्त की है। वे देश के सामने मौजूद गंभीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 9 दिसंबर, 2024 को बांग्लादेश में एक दिवसीय यात्रा के दौरान 'स्पष्ट, ईमानदार और रचनात्मक विचारों का आदान-प्रदान' किया, जिसमें उन्होंने युनुस, विदेश मामलों के सलाहकार और विदेश सचिव से मुलाकात की।

यह कूटनीतिक भाषा इस बात की ओर इशारा करती है कि मिसरी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और 'संस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक संपत्तियों पर हमलों' के कारण भारत की चिंताओं को बयां किया, और इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं छिपाई।

बांग्लादेश में असंतोष का माहौल

युनुस सरकार अब तक देश के प्रमुख समस्याओं से निपटने में सफल नहीं हो पाई है। अब तक, युनुस और उनकी टीम ने आवश्यक नेतृत्व का प्रदर्शन नहीं किया है। जिस तरह से स्थिति विकसित हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के कई सदस्य चुनावों के दौरान चुनाव जीत सकते हैं। युनुस पर, विशेष रूप से BNP से, जल्दी चुनाव कराने का दबाव है। यदि BNP और जमात-ए-इस्लामी बड़े पैमाने पर चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं, तो यह देश के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। खासकर जमात-ए-इस्लामी का इतिहास काफी विवादास्पद है। इसने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण का विरोध किया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों में लिप्त था। इसके बावजूद, राजनीतिक स्वार्थ के कारण इसे राजनीति में पुनः प्रवेश करने का अवसर मिला, खासकर BNP द्वारा। इस उत्थल-पुथल के बीच, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की अधिकांश जनसंख्या भारत

के साथ अच्छे संबंधों का समर्थन करती है। वे एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन का समर्थन करते हैं, जो शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

हालाँकि, अंतरिम सरकार के कुछ तत्व और जमात-ए-इस्लामी जैसे समूह, जो भारत विरोधी भावनाएँ रखते हैं, वह समाज के उग्र और कट्टरपंथी तत्वों का हिस्सा हैं। इनमें से कई लोग जो पहले जेल में थे, शेख हसीना की निर्वासन के बाद रिहा हुए हैं और अब वे भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक भावनाओं को उकसाने में लगे हुए हैं। ये समूह बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष, मिश्रित संस्कृति को बदलने और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम की भावना को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश को शरिया कानून से शासित एक इस्लामी राज्य में बदला जा सके। बांग्लादेश के लोगों के लिए यह बेहद आवश्यक है कि वे मौजूदा अराजकता और कानून के अभाव के बीच यह सुनिश्चित करें कि देश के लोकतांत्रिक, विविधतापूर्ण और सहिष्णु सामाजिक ताने-बाने को कोई स्थायी नुकसान न पहुंचे।

देश की अर्थव्यवस्था के बुरे हालात और गिरावट के बीच, युनुस को यह समझ में आ रहा होगा कि शुरू में लोगों द्वारा उनके और उनके सलाहकारों को दी गई सहानुभूति तेजी से खत्म हो रही है। उनका जन समर्थन शायद कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएगा।

भारत-बांग्लादेश संबंध

भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और कई अन्य समानताओं के कारण एक मजबूत संबंध है। हालांकि, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन द्विपक्षीय संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से पिछले 15 वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से सुधार हुआ। यह संबंध सम्प्रभुता, समानता, विश्वास और समझ पर आधारित एक समग्र साझेदारी के रूप में विकसित हुए थे। यह संबंध पूरे क्षेत्र और उससे बाहर के लिए द्विपक्षीय संबंधों का एक आदर्श बन गए थे।

पिछले 15 वर्षों में, दोनों देशों ने मिलकर आतंकवादी समूहों का मुकाबला किया, एक जटिल सीमा और समुद्री मुद्दे को हल किया और कई बुनियादी ढांचा और ऊर्जा सौदों पर हस्ताक्षर किए। इन सभी प्रगति ने दोनों देशों के आपसी लाभ को बढ़ावा दिया और उन्हें दशकों बाद एक-दूसरे के और करीब ला दिया था।

हालाँकि, अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद सब कुछ बदल गया। आज भारत-बांग्लादेश संबंध गंभीर संकट में हैं।

हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में विशेष रूप से हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर कई साम्प्रदायिक हमले हुए। इन घटनाओं में मंदिरों, घरों और दुकानों पर हमले, लूटपाट और हत्याएं शामिल हैं, जो बांग्लादेश के विभिन्न जिलों में हुईं। 16 अगस्त 2024 को जब डॉ. युनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की, तो मोदी ने बांग्लादेश में हिंदू और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण का मुद्दा उठाया। डॉ. युनुस ने हिंदू और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ये केवल शब्द ही साबित हुए हैं। युनुस और उनके अधिकारियों ने यह कहा कि मीडिया की रिपोर्ट्स में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, जिससे अपराधियों को और बढ़ावा मिला है और वे बिना किसी डर के अपनी हिंसा जारी रख रहे हैं। बांग्लादेश की कुछ एजेंसियों द्वारा की गई जांच के अनुसार, हसीना के देश छोड़ने के बाद से 2,000 से अधिक हमले हुए हैं, जिनमें व्यक्तिगत हमले, हत्याएं, अपहरण, बलात्कार और संपत्ति की नष्ट हो रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय देशों के कानून निर्माताओं और नागरिक समाज नेताओं ने अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अब अंतरिम सरकार यह तर्क नहीं दे सकती कि ये घटनाएँ 'अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही हैं' या यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है।

हाल ही में हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया है। सामान्य लोगों में असहिष्णुता और भारत-विरोधी भावनाओं की गहराई का अंदाजा इस बात से लगता है कि चिन्मय दास का केस किसी वकील को लेने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वकीलों के संघ ने प्रतिशोध के डर से यह धमकी दी थी। भारत की गंभीर चिंता और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग के जवाब में, युनुस ने बार-बार यह कहा कि हमले 'साम्प्रदायिक' नहीं थे, बल्कि राजनीतिक कारणों से हुए थे क्योंकि हिंदू मुख्य रूप से एएल (आल बंगाल अवामी लीग) समर्थक माने जाते हैं। यह उन लोगों के लिए कोई सांत्वना या न्याय नहीं हो सकता जो हमलों का शिकार हो रहे हैं, या जिनके घरों, पूजा स्थलों और कार्यस्थलों को लूटा या जलाया जा रहा है।

समस्याओं को और बढ़ाते हुए, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। 11 नवंबर 2024 को 53 वर्षों में पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए पहली बार एक मालवाहक जहाज चिटगांव बंदरगाह पर उतरा। अक्टूबर में, बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान से आयात पर अनिवार्य शारीरिक निरीक्षण को समाप्त कर दिया। इन घटनाओं को 2004 में चिटगांव में पकड़े गए हथियारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उस समय 1,500 बॉक्स चीनी गोला-बारूद बरामद हुआ था, जिनकी कीमत लगभग 4.5-7 मिलियन डॉलर थी, और इन्हें प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के लिए भेजा जाना था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (ISI) द्वारा साजिश रची गई मानी जाती थी। इसके अलावा, युनुस सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा के लिए आवेदन करने से पहले सुरक्षा क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को भी हटा दिया। सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से अपनी मुलाकात में युनुस ने द्विपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इन घटनाओं से भारत के लिए बांग्लादेश से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और बढ़ गई हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में कुछ विश्लेषकों का यह आरोप है कि भारत ने शेख हसीना की सरकार को समर्थन देकर गलती की। यह कथन सही स्थिति का भ्रामक विश्लेषण है। भारत को बांग्लादेश में सत्ता में किसी भी सरकार के साथ संवाद करना था, और शेख हसीना बांग्लादेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई प्रधानमंत्री थीं। भारत भविष्य में भी बांग्लादेश में जो भी सरकार होगी, उसके साथ संवाद बनाए रखेगा। दोनों देशों द्वारा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में किए गए सभी निर्णय दोनों देशों के लोगों के आपसी लाभ के लिए थे, न कि किसी विशेष नेता या देश के व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिए। भारत द्वारा शुरू किए गए सभी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बांग्लादेश के लोगों की भलाई के लिए जारी हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने बांग्लादेश के सभी विभिन्न राजनीतिक समूहों, जिनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) भी शामिल है, से संवाद किया है।

भारत की 'पड़ोसी पहले नीति' के तहत, भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ एक गैर-प्रतिसादी और उदार नीति अपनाई है। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ बांग्लादेश को ही हुआ है, जहां भारत ने 8 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता और अनुदान प्रदान किया है। बांग्लादेश भारत की कई प्रमुख विदेश नीति योजनाओं का

केंद्रीय बिंदु है - 'एक्ट ईस्ट नीति', SAGAR (सागर) सिद्धांत, और इसके इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

9 दिसंबर को बांग्लादेश यात्रा के दौरान, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने सभी संवाददाताओं से कहा, 'भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और आपसी लाभकारी संबंधों की कामना करता है। हमने अतीत में हमेशा और भविष्य में भी इस संबंध को एक जनकेंद्रित और जनोन्मुख संबंध के रूप में देखा है।' उन्होंने व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल, विकास सहयोग, कांसुलर सहयोग और सांस्कृतिक सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर आपसी लाभकारी संबंधों की बात की और आश्वस्त किया कि यह संबंध भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंधों की कामना करता है। विदेश सचिव मिस्री ने बांग्लादेश के संवाददाताओं को भारत की 'रेडलाइन' के बारे में स्पष्ट संदेश दिया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत को निशाना बनाने वाले उग्रवादी तत्वों को शरण न देने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह आवश्यक है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यह समझे कि भारत के साथ सकारात्मक संबंध बांग्लादेश और इसके लोगों के लिए शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बेहद लाभकारी हैं।

> **भारत की 'रेडलाइन' के बारे में स्पष्ट संदेश दिया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत को निशाना बनाने वाले उग्रवादी तत्वों को शरण न देने की आवश्यकता पर जोर दिया।**

युनुस ने मिस्री से अपनी मुलाकात में यह कहा कि शेख हसीना के दिल्ली से अंतरिम सरकार के खिलाफ बयान समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने मिस्री से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा सीमा पर मारे गए लोगों के कथित मामले, व्यापारिक रुकावटें, गंगा जल समझौते का नवीनीकरण, तीस्ता नदी के पानी की साझेदारी, आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सुविधाओं, नेपाल और भूटान से बांग्लादेश के लिए जल विद्युत आपूर्ति आदि के विषय शामिल थे। ये सभी मुद्दे और अधिक यह स्पष्ट करते हैं कि बांग्लादेश भारत पर अत्यधिक निर्भर है।

बांग्लादेश में सरकार के बदलाव और पिछले चार महीने में हुई घटनाएं भारत के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं। भारत पहले ही अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर दो शत्रु शक्तियों का सामना कर रहा है। यदि बांग्लादेश भी पूर्वी सीमा से एक शत्रु बनकर उभरता है, तो यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकता है। अभी तक बांग्लादेश की सीमा BSF (सीमा सुरक्षा बल) द्वारा संरक्षित की जा रही है। आने वाले महीनों में भारत को यह विचार करना होगा कि क्या उसे बांग्लादेश से लगी छह राज्यों की सीमा पर अपनी सेना भी तैनात करनी चाहिए।

युनुस और उनके सलाहकारों का समूह इस विकसित हो रही स्थिति से निपटने में पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत हो रहा है। या तो वे अक्षम हैं, या फिर, और भी खराब स्थिति में, वे जो हो रहा है, उसमें भागीदार हैं। उन्हें आपसी निर्भरता के महत्व को समझना चाहिए। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स के अधिकांश निर्यात भारत से आयात होने वाले मध्यवर्ती और इनपुट्स पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश के अधिकांश निर्यात भारतीय बंदरगाहों से वैश्विक बाजारों में जाते हैं। बांग्लादेश की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी अधिकांशतः भारत से ही होती है। दोनों देशों के लिए यह आपसी हित में है कि उनके रिश्ते अच्छे रहें। बांग्लादेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उग्रवाद, इस्लामवाद और जिहादी तत्वों का हब न बने। उसे पाकिस्तान के उदाहरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए, जो आतंकवाद का केंद्र बन गया। बांग्लादेश और इसके लोगों के लिए सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक प्रगति की आवश्यकता है। भारत इस दिशा में बांग्लादेश का सबसे अच्छा साझेदार हो सकता है। भारत ने बांग्लादेश को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उसे भारत की सुरक्षा और हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए। भारत को आने वाले हफ्तों और महीनों में बांग्लादेश की घटनाओं पर कड़ी नजर रखनी होगी और आवश्यकता अनुसार कदम उठाने होंगे।

अशोक सज्जनहार, कजाकिस्तान, स्वीडन और लातविया में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इन्होंने वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स, मास्को, जिनेवा, तेहरान, ढाका और बैंकॉक में राजनयिक पदों पर कार्य किया है, वर्तमान में नई दिल्ली में ग्लोबल स्टडीज संस्थान के अध्यक्ष हैं और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के कार्यकारी परिषद सदस्य हैं।

बांग्लादेश: राजनीतिक अस्थिरता और सामरिक महत्व

जलज श्रीवास्तव

बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में अस्थिर बनी हुई है। देश महंगाई, प्रदर्शनों और लोकतांत्रिक सुधारों की बढ़ती मांगों का सामना कर रहा है। इस राजनीतिक उथल-पुथल, जिसमें सरकार के अधिनायकवादी रुझानों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, से देश की वैश्विक छवि पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। भारत के दृष्टिकोण से, बांग्लादेश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करती है।

आर्थिक दृष्टिकोण से, बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में काफी प्रभावशाली विकास किया है। इसके सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है, यहां तक कि महामारी के दौरान भी। 2020 में यह वृद्धि दर 3.4% थी, जबकि 2021 में 6.9% और 2022 में 7.2% रही। बांग्लादेश 2026 तक एक विकासशील देश बनने और 2041 तक उच्च-आय वाले देश की स्थिति प्राप्त करने की योजना बना रहा था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बांग्लादेश को ऐसे साझेदारियों का लाभ उठाना जारी रखना होगा जो इसके विकास में सहायक हों।

निष्कर्षतः, जबकि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करती है, इसका सामरिक महत्व इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अतुलनीय है। भारत को बांग्लादेश के साथ स्थिर संबंधों को प्राथमिकता देते हुए देश के आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से निपटना चाहिए। बांग्लादेश के आर्थिक लक्ष्यों और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह अपनी राजनीतिक स्थिति को कैसे प्रबंधित करता है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को कैसे बनाए रखता है।

सपाट धरती के पैरोकारों का पाखंड

कुछ कट्टरपंथी मजहबी विद्वान कुरआन की आयतों की गलत व्याख्या कर यह दावा करते हैं कि 'पृथ्वी सपाट है'- यह एक 'विचार' है, जो मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच को कमजोर करती है। इन अवैज्ञानिक दावों या कहें तथाकथित 'विचार' ने न केवल मुस्लिम समाज की प्रगति को बाधित किया है, बल्कि आधुनिक विज्ञान के प्रति शत्रुता और अज्ञानता का माहौल भी बनाया है। यह आवरण कथा इस बात पर जोर देता है कि इस्लाम का असल संदेश ज्ञान, सहिष्णुता और तर्कशीलता का है, जिसे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है...

श्रीरेजेश

मजहबी आस्था का मुख्य उद्देश्य मानवता के कल्याण, नैतिकता और शांति को बढ़ावा देना है। लेकिन जब यह आस्था पाखंड और कट्टरपंथ के जाल में फंस जाती है, तो इसका उपयोग हिंसा और आतंक के लिए होने लगता है। यह केवल फ्रेडरिक नीत्शे और इब्न रश्द जैसे दार्शनिकों की चिंता नहीं थी, बल्कि आज का भी एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। चाहे वह पश्चिमी देशों में मजहबी पाखंड हो या इस्लामी कट्टरपंथ, हर जगह इसका नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी पुस्तक 'Thus Spoke Zarathustra' में मजहबी संस्थाओं और उनके अंधविश्वास की कठोर आलोचना की थी। उनका प्रसिद्ध उद्धरण, 'God is dead. God remains dead. And we have killed him,' मजहब के नाम पर फैले पाखंड और अंधविश्वास की ओर इशारा करता है। नीत्शे का कहना था कि मजहबी संस्थाओं ने मानव की स्वतंत्र सोच और सृजनात्मकता को बाधित किया है, और यह दावा किया कि मजहब ने लोगों को डर और नैतिक जंजीरों में बाँध रखा है।

वहीं इस्लामी दार्शनिक इब्न रश्द (एवरोस) ने भी इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनकी प्रसिद्ध उक्ति, 'Ignorance leads to fear, fear leads to hatred, and hatred leads to violence,' दर्शाती है कि अज्ञानता और अंधविश्वास लोगों को कट्टरपंथ की ओर ले जाते हैं। इब्न रश्द ने इस्लामिक समाज में तार्किकता और

विज्ञान के महत्व पर जोर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके विचारों को ज्यादा समर्थन नहीं मिला।

आज के समय में हम जिस मजहबी कट्टरता और अंधविश्वास का सामना कर रहे हैं, वह न केवल नीत्शे और इब्न रश्द की भविष्यवाणियों को सही ठहराता है, बल्कि यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते संघर्ष और हिंसा की भी जड़ है।

इस्लाम, जिसका शाब्दिक अर्थ 'शांति और समर्पण' है, इसने हमेशा न्याय, भाईचारे और दया की शिक्षा दी है। लेकिन इस्लाम के नाम पर काम करने वाले कट्टरपंथी समूहों ने इस्लाम की शिक्षाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। अल-कायदा, आईएसआईएस, तालिबान, और बोको हराम जैसे संगठनों ने आतंक और हिंसा का सहारा लेते हुए निर्दोष लोगों की हत्या की है।

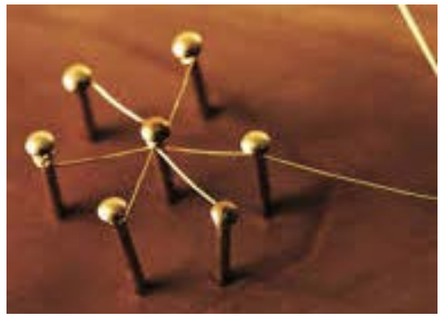

कुछ कट्टरपंथी समूहें ने ग्रंथों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं ताकि वे अपने हिंसात्मक एजेंडे को उचित ठहरा सकें। इन चरमपंथी गतिविधियों ने इस्लाम की वास्तविक छवि को धूमिल कर दिया है।

कट्टरपंथियों ने इस्लामी सिद्धांत जिहाद की गलत व्याख्या की है। जबकि जिहाद का वास्तविक अर्थ आत्म-सुधार और अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष है, कुछ चरमपंथी इसे हिंसा और आतंक का औचित्य ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरआन में निर्दोष लोगों की हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है:

'जिसने किसी निर्दोष को मारा, उसने पूरी मानवता को मारा।' (कुरआन 5:32)

इसके बावजूद, कुछ कट्टरपंथी समूह और नेता मजहबी ग्रंथों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं ताकि वे अपने हिंसात्मक एजेंडे को उचित ठहरा सकें। इन चरमपंथी गतिविधियों ने इस्लाम की वास्तविक छवि को धूमिल कर दिया है, और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के प्रति घृणा और भेदभाव बढ़ा है।

आज हम पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक, और दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप तक, विभिन्न देशों में इस्लाम के नाम पर हिंसा, युद्ध और आतंकवाद देख रहे हैं। यह स्थिति केवल उस गलतफहमी को और बढ़ाती है कि इस्लाम हिंसात्मक मजहब है, जबकि इस्लाम का वास्तविक संदेश शांति, न्याय और करुणा का है। कट्टरपंथी विचारधारा ने मुस्लिम समाज के भीतर भी विभाजन को बढ़ावा दिया है, जहां कुछ वर्गों को लगता है कि वे सच्चे मुसलमान हैं, जबकि अन्य को मजहब के बाहर का समझा जाता है।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष, जैसे कि सीरिया, इराक और यमन में गृहयुद्ध, ने न केवल इन देशों को तबाह कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की छवि को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वहीं, यूरोप में हुए आतंकवादी हमलों ने इस्लामोफोबिया को और बढ़ावा दिया है, जिससे मुसलमानों के प्रति नकारात्मक धारणाएं और भेदभाव पैदा हुआ है।

भारत, जो अपनी विविधता और बहुलता के लिए जाना जाता है, वहां भी इस्लामी कट्टरपंथ के कुछ मामले सामने आए हैं। तीन तलाक और हिजाब विवाद जैसे मुद्दे यह दर्शाते हैं कि कैसे इस्लाम के कुछ रूढ़िवादी हिस्से मजहबी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा प्रगतिशील और आधुनिक विचारों को अपनाने का समर्थन करता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी समाज को पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।

इसके अलावा, कुछ भारतीय युवाओं के अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के प्रयासों ने भी भारत में मुसलमानों की छवि को प्रभावित किया है। आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों ने भारतीय मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

दुनिया के कई हिस्सों में, महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल एक औजार के रूप में किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन इसका सबसे प्रबल उदाहरण है, जहां महिलाओं को शिक्षा, कामकाज और सार्वजनिक जीवन से लगभग वंचित कर दिया गया है। यह विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब इस्लाम की मूल शिक्षाओं पर नजर डाली जाती है। पैगंबर मुहम्मद ने स्पष्ट रूप से कहा है, 'ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान (पुरुष और महिला) पर अनिवार्य है।' फिर भी, मजहबी व्याख्याओं और सत्ता की राजनीति ने इस मूल संदेश को विकृत कर दिया है।

आज कुछ मजहबी विद्वान और चरमपंथी समूह इस्लाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। वे इस्लाम की शिक्षाओं को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं, जिससे समाज में असहिष्णुता, पाखंड और कट्टरता का प्रसार होता है। अफसोस की बात है कि समाज के कई हिस्सों में लोग इन भ्रामक व्याख्याओं को चुनौती देने से कतराते हैं।

एक विचित्र उदाहरण इस्लामिक शिक्षाओं के नाम पर पृथ्वी को चपटी और स्थिर कहने की है। कुछ मजहबी विद्वानों जिन्हें आमतौर पर बोलचाल की भाषा मौलाना कहते हैं, उन्होंने कुरआन की आयतों की गलत व्याख्या कर इस धारणा को प्रचारित किया है। उदाहरण के लिए, सूरह अन-नाज़िआत (79:30) और सूरह अल-ग़ाशियाह (88:20) में 'पृथ्वी को बिछाने' की बात कही गई है, जिसे पृथ्वी के सपाट होने का सबूत बताया जाता है। जबकि, यह अधिक संभावना है कि यह शब्दावली पृथ्वी को मानव जीवन के लिए अनुकूल और सुरक्षित बनाने के रूपक के रूप में उपयोग की गई है।

इतिहास में मुस्लिम विद्वानों ने विज्ञान और खगोलशास्त्र में अद्वितीय योगदान दिया है। अल-फ़रग़ानी और अल-बरूनी जैसे विद्वानों ने पृथ्वी के गोलाकार होने का समर्थन किया और उसकी माप भी की। कुरआन में सूरह अज़-ज़ुमर (39:5) में कहा गया है, 'वह रात को दिन में लपेटता है और दिन को रात में लपेटता है,' जो स्पष्ट रूप से पृथ्वी के गोलाकार होने की ओर संकेत करता है। यह उदाहरण बताता है कि इस्लाम में वैज्ञानिक ज्ञान और तर्कशीलता का कितना महत्व है।

हालांकि, सिर्फ यहीं नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां मुस्लिम समाज में इस कदर फैलायी गई हैं कि यह उनके अवचेतन में गहरे तक पैबस्त हो गई हैं। यह दावा कुरआन की व्याख्या में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी और ऐतिहासिक संदर्भों की अनदेखी पर आधारित है। इस तरह की गलत व्याख्याएं मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच को कुंद कर रही हैं, जाहिलियत को बढ़ावा दे रही हैं, और आधुनिक समाज में सामाजिक सद्भाव को खतरे में डाल रही हैं। अति-रूढ़िवादी विद्वानों ने इन आयतों की गलत व्याख्या करते हुए दावा किया है कि इससे पृथ्वी के सपाट होने का संकेत मिलता है। हालांकि, यह तर्क न केवल वैज्ञानिक प्रमाणों के विपरीत है, बल्कि आधुनिक इस्लामी विद्वान और वैज्ञानिक स्वयं इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि कुरआन की यह भाषा प्रतीकात्मक और रूपक है, न कि वैज्ञानिक रूप से शाब्दिक।

इसके बावजूद, कुछ लोग इस्लाम के भीतर इस दावे को मजहबी

रूप से सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जिससे मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास रुक जाता है। ऐसे विचारों का प्रसार मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक अन्वेषण और तार्किकता के प्रति उदासीनता को बढ़ावा देता है। जबकि इस्लाम का प्रारंभिक इतिहास विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है—जैसे खगोलशास्त्री अल-बिरूनी और चिकित्सा विशेषज्ञ इब्न सीना। आज इन कट्टरपंथी विचारों ने उस विरासत को कमजोर कर दिया है।

पृथ्वी के सपाट होने का दावा, केवल दावा भर नहीं है बल्कि यह एक विचार का रूप ले चुका है और यह उन सभी वैज्ञानिक तथ्यों के खिलाफ जाता है जो पृथ्वी के गोलाकार होने जैसी वैज्ञानिक सोच के पैरोकार हैं। यह भी दर्शाता है कि यह समुदाय आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझने और अपनाने में पिछड़ रहा है। इससे विज्ञान के प्रति शत्रुता और संदेह का माहौल बनता है, जो युवा पीढ़ी को आधुनिक विज्ञान के अध्ययन और समझ से दूर कर रहा है। जब समाज में मजहबी किताबों की गलत व्याख्या के आधार पर ऐसी अवैज्ञानिक धारणाओं को सही ठहराया जाता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि अज्ञानता (जाहिलियत) बढ़ती है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को तार्किक और विवेकशील बनाना है, परंतु जब शिक्षा का स्थान मजहबी कट्टरता और अंधविश्वास लेते हैं, तो समाज में बौद्धिक स्थिरता आ जाती है। ऐसे विचार न केवल लोगों के वैज्ञानिक सोच को बाधित करते हैं, बल्कि उन्हें जड़ता और अंधविश्वास की ओर धकेल देते हैं।

इसके अतिरिक्त, जब युवा मुसलमानों को यह सिखाया जाता है कि पृथ्वी सपाट है और आधुनिक विज्ञान गलत है, तो इससे उनका भविष्य में वैज्ञानिक विषयों में योगदान कम हो जाता है। इससे इस्लामी समाज में शिक्षा का स्तर गिरता है और वैश्विक ज्ञान की दौड़ में मुस्लिम समाज पीछे छूटता जाता है। ऐसे अवैज्ञानिक दावों का प्रचार न केवल मुस्लिम समाज के भीतर विभाजन पैदा करता है, बल्कि यह मुस्लिम और गैर-मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद और सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाता है।

जब एक समाज आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों को स्वीकार करने से इनकार करता है और मजहब की गलत व्याख्या पर जोर देता है, तो यह अंतर-सांस्कृतिक संवाद के लिए मुश्किलें पैदा करता है। गैर-मुस्लिम समाज इस्लाम को कट्टरपंथी और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखने लगते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और बढ़ता है। इससे मुस्लिम समाज में आंतरिक संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं, जहां एक तरफ प्रगतिशील मुस्लिम विद्वान और वैज्ञानिक समाज सुधार और आधुनिकता का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ रूढ़िवादी मजहबी विद्वान पुरानी, अवैज्ञानिक मान्यताओं को बनाए रखने पर जोर देते हैं। यह आंतरिक विभाजन मुस्लिम समाज को कमजोर करता है और उसकी एकता और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं को समझने और उनका पालन करने की सख्त आवश्यकता है। यह मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि वह कट्टरता, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाए। इस्लामी विद्वानों को चाहिए कि वे कुरआन और हदीस की शिक्षाओं की वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण व्याख्या करें, ताकि समाज में फैली गलतफहमियों को दूर किया जा सके।

इस्लाम, जैसा कि पैगंबर मुहम्मद ने प्रचारित किया, एक ऐसा मजहब है जो समानता, सहिष्णुता और ज्ञान को महत्व देता है। यदि इस्लामी समाज इस मूल संदेश को अपनाए, तो यह न केवल महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करेगा बल्कि इस्लाम के वास्तविक उद्देश्य — प्रेम, शांति और करुणा — को भी स्थापित करेगा।

इस्लाम के नाम पर कुछ मौलानाओं और कट्टरपंथी मजहबी नेताओं द्वारा प्रसारित अति रूढ़िवादी विचारों ने आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक नकारात्मक छवि गढ़ दी है। यह प्रवृत्ति न केवल इस्लाम के वास्तविक संदेश को विकृत कर रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मुसलमानों को एक खतरनाक समुदाय के रूप में पेश कर रही है। कई घटनाएं और स्थितियां इस प्रक्रिया को दर्शाती हैं, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे अति-रूढ़िवादी विचारधाराएं मुस्लिम समाज के भीतर और बाहर गंभीर चुनौतियां पैदा कर रही हैं।

कई मौलानाओं द्वारा प्रचारित कट्टरपंथी विचारधारा इस्लाम के नाम पर हिंसा, असहिष्णुता और सामाजिक अलगाव को बढ़ावा देती है। यह कट्टरपंथी विचारधारा दुनिया के कई हिस्सों में फैली है, खासकर पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी अफ्रीका, और कुछ पश्चिमी देशों में भी, जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं। इन विचारों का समर्थन करने वाले मजहबी नेता इस्लाम की उन शिक्षाओं को अनदेखा करते हैं जो शांति, सहनशीलता और

पारस्परिक सद्भाव का समर्थन करती हैं। इसके विपरीत, वे शरिया कानून की कठोर व्याख्या और गैर-मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाते हैं, जिससे वैश्विक समाज में मुसलमानों की एक रूढ़िवादी और हिंसक छवि बनती है। यहां कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं जिसे उदाहरण के दौर पर देखा-समझा जा सकता है।

2021 में, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा इस्लामी दुनिया में अति-रूढ़िवादी विचारों के प्रसार का प्रमुख उदाहरण है। तालिबान ने शरिया कानून के अपने कठोर और कट्टरपंथी संस्करण को लागू किया, जिसके तहत महिलाओं के अधिकारों का दमन, शिक्षा पर प्रतिबंध, और सामाजिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया गया। इस्लाम के इस तरह के कट्टरपंथी और हिंसात्मक रूप को देखकर दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों के प्रति नकारात्मक धारणा बन गई, जिसमें उन्हें वैश्विक शांति के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा।

अति-रूढ़िवादी विचारधारा का सबसे विनाशकारी परिणाम आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के रूप में सामने आता है। अल-कायदा, आईएसआईएस, बोको हराम और अन्य चरमपंथी संगठनों ने इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाया है। ये समूह कुरआन और इस्लामी शिक्षाओं की विकृत व्याख्या करके जिहाद का गलत अर्थ निकालते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। इस तरह की घटनाओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न किया है, और पश्चिमी देशों में मुसलमानों के प्रति संदेह और घृणा की भावना बढ़ी है।

आईएसआईएस ने 2014 में एक 'खिलाफत' की घोषणा की और सीरिया तथा इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस संगठन ने इस्लाम के नाम पर भयावह हिंसा, नरसंहार, और बर्बरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल गैर-मुसलमानों को बल्कि शिया मुस्लिमों, यज़ीदियों, और अन्य मजहबी अल्पसंख्यकों को

भी निशाना बनाया। यह संगठन मुस्लिम युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी गतिविधियों में भर्ती करने में सफल रहा। आईएसआईएस के बर्बर कारनामों ने इस्लाम की छवि को पूरी दुनिया में धूमिल किया और मुसलमानों को एक खतरनाक समूह के रूप में देखा जाने लगा।

2015 और 2016 में पेरिस और ब्रुसेल्स में हुए आतंकवादी हमलों ने यूरोप में मुसलमानों की छवि को और खराब कर दिया। आईएसआईएस के समर्थकों द्वारा किए गए इन हमलों ने न केवल यूरोपीय समाज में भय और घृणा का माहौल पैदा किया, बल्कि इस्लाम को हिंसा और आतंकवाद से जोड़ दिया गया। इस तरह के हमलों के कारण यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों में वृद्धि देखी गई, और उनके प्रति नकारात्मक धारणाएं और मजबूत हो गईं।

अति-रूढ़िवादी मौलानाओं द्वारा प्रचारित विचार महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करते हैं, जो आधुनिक समाज के मूल्यों और अधिकारों के खिलाफ है। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सहभागिता पर प्रतिबंध लगाकर इन कट्टरपंथियों ने इस्लाम को एक ऐसे मजहब के रूप में प्रस्तुत किया है जो महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। जबकि इस्लाम महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, और स्वतंत्रता का समर्थन करता है, कट्टरपंथी विचारधारा इसका विपरीत प्रभाव डालती है।

अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के तहत लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध ने न केवल मुस्लिम समाज के भीतर असंतोष पैदा किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। महिलाओं के अधिकारों के इस हनन ने दुनिया भर में इस्लाम के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया, जहां इसे एक ऐसे मजहब के रूप में देखा जाने लगा जो महिलाओं की स्वतंत्रता को दबाता है।

अति-रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण इस्लामोफोबिया (इस्लाम के प्रति भय और घृणा) का विश्व स्तर पर तेजी से विस्तार हुआ है। जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों से जुड़े हिंसक हमलों और कट्टरपंथी गतिविधियों की खबरें आती हैं, तो गैर-मुस्लिम समुदायों के बीच मुसलमानों के प्रति नकारात्मक धारणाएं बढ़ती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि दुनिया के कई देशों में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह स्थिति न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि भारत जैसे देशों में भी देखी जाती है, जहां मुसलमानों के प्रति साम्प्रदायिकता और विभाजन की राजनीति होती है।

9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद से अमेरिका और यूरोप में

इस्लामोफोबिया का उभार हुआ है। मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़कर देखा जाने लगा, और उनके खिलाफ भेदभाव और घृणा अपराधों में वृद्धि हुई। मुस्लिम आव्रजकों के खिलाफ सख्त नीतियों को लागू किया गया, और कई देशों में मस्जिदों पर हमले हुए। इन घटनाओं ने मुस्लिम समुदायों को अलग-थलग कर दिया और उनके प्रति सामाजिक सद्भावना को नष्ट कर दिया।

अति-रूढ़िवादी विचारधाराओं ने कई मुस्लिम देशों में राजनीति और मजहब को आपस में मिला दिया है, जिससे हिंसक सत्ता संघर्ष और अस्थिरता उत्पन्न हुई है। कुछ कट्टरपंथी समूह इस्लाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन बढ़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि इन देशों में स्थायी संघर्ष और अस्थिरता बनी रहती है, जिससे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मुसलमानों के प्रति नकारात्मक धारणाएं गहराती हैं।

ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में मजहब का राजनीति पर गहरा प्रभाव है। इन देशों में शरिया कानून के कठोर पालन और मजहबी नेतृत्व की अत्यधिक शक्ति ने वैश्विक समाज में इस्लाम को एक रूढ़िवादी और कठोर मजहब के रूप में देखा जाता है। मजहबी स्वतंत्रता की कमी और विरोधियों के प्रति कठोर दमन ने इस छवि को और मजबूत किया है।

अगर भारत की बात करें तो यहां भी इस्लामी रूढ़िवाद और कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रभाव ने कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों को जन्म दिया है। हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि भारत एक बहुलतावादी और विविधतापूर्ण समाज है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के मुसलमानों ने देश की प्रगति और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, लेकिन कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण भारत में भी मुसलमानों की छवि प्रभावित हुई है। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम समुदाय को लेकर बन रही नकारात्मक धारणाओं से भी जुड़ी हुई है।

भारत में कुछ मौलानाओं और कट्टरपंथी मजहबी नेताओं द्वारा प्रसारित कठोर और रूढ़िवादी इस्लामी विचारधाराएं भारतीय मुसलमानों की छवि को प्रभावित करती हैं। ये विचारधाराएं महिलाओं की शिक्षा, आधुनिकता, और मुस्लिम समुदाय की मुख्यधारा में सहभागिता को कम करने की प्रवृत्ति रखती हैं। उदाहरण के लिए, तीन तलाक जैसे मुद्दों पर इस्लामी कट्टरपंथियों का विरोध आधुनिक सुधारों के प्रति उनके नकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। भारतीय समाज में यह धारणा बनी है कि मुस्लिम समुदाय में आधुनिकता के प्रति अस्वीकार्यता अधिक है, और यह उनके मुख्यधारा से कटने का एक बड़ा कारण है।

भारत में तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने 2019 में एक कानून पारित किया, जिसका कई रूढ़िवादी मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने विरोध किया। उनका तर्क था कि यह इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन है, जबकि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। इसी प्रकार, समान नागरिक संहिता पर चल रही बहस में भी कट्टरपंथी इस्लामी नेता किसी भी प्रकार के सुधार का विरोध करते हैं। इससे भारतीय मुसलमानों की प्रगतिशीलता पर सवाल उठते हैं और उनकी छवि को नुकसान होता है।

भारत में आतंकवाद और मुस्लिम युवाओं के कट्टरपंथ की ओर झुकाव ने भी मुसलमानों की छवि को नुकसान पहुंचाया है। कुछ इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों ने भारतीय मुसलमानों के बीच जिहादी विचारधारा का प्रसार करने की कोशिश की है, जो न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि भारतीय मुसलमानों की एक नकारात्मक छवि भी गढ़ता है। आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों ने भारतीय मुस्लिम युवाओं को भी कट्टरपंथी बनाने का प्रयास किया है।

भारत में कई आतंकवादी हमलों के पीछे कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों का हाथ रहा है, जैसे 2008 का मुंबई हमला, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा शामिल था। इस तरह के हमलों ने भारत में मुसलमानों के प्रति नकारात्मक धारणाओं को जन्म दिया है। इसके अलावा, कुछ भारतीय मुस्लिम युवाओं के आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के प्रयास भी इस छवि को मजबूत करते हैं कि इस्लाम के नाम पर हिंसा और आतंकवाद बढ़ रहा है।

भारत में इस्लाम के नाम पर मजहबी कठमुल्लापन ने सामाजिक सद्भाव को भी कमजोर किया है। कट्टरपंथी विचारधाराएं भारतीय समाज में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती हैं। मजहबी संगठनों द्वारा किए गए उकसावेपूर्ण बयान और नीतियों के खिलाफ उठाए गए कदमों का विरोध, जैसे कि स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर विवाद, इस्लामी रूढ़िवाद को और अधिक बढ़ावा देते हैं। इससे मुसलमानों के खिलाफ संदेह और भेदभाव की भावना बढ़ती है और उनका सामाजिक अलगाव बढ़ता है।

2022 में कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। इस मुद्दे ने पूरे भारत में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कट्टरपंथी मौलाना और संगठनों ने इसे मजहबी स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि विरोधियों ने इसे आधुनिकता और शिक्षा से जोड़कर देखा। इस विवाद ने भारतीय समाज में मुसलमानों के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जहां कट्टरपंथ को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाने लगा।

वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे इस्लामोफोबिया का असर भारत में भी देखने को मिलता है। कई कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की गतिविधियों और आतंकी हमलों के कारण भारत में मुसलमानों के प्रति नकारात्मक धारणाएं बढ़ी हैं। मुसलमानों के प्रति भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, और हिंसात्मक घटनाएं भी इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देती हैं। इसके परिणामस्वरूप, मुस्लिम समुदाय को अक्सर अलग-थलग महसूस होता है, और वे सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक रूप से हाशिये पर चले जाते हैं।

हाल के वर्षों में भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को कथित गोरक्षा या मजहबी कारणों से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा, सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मुसलमानों को 'देश-विरोधी' और 'आतंकवादी' के रूप में देखा गया, जिससे उनकी स्थिति और कठिन हो गई। इन घटनाओं ने भारत में मुसलमानों के प्रति भेदभाव और घृणा को और गहराया है।

वैश्विक स्तर पर मुस्लिम देशों में हो रहे संघर्षों और कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रभाव भारत में भी देखा जाता है। जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, और तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की नीतियों ने भारतीय मुसलमानों के बीच भी इस्लामी कट्टरपंथ को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, कुछ भारतीय मुसलमान वैश्विक इस्लामी आंदोलनों से प्रभावित होकर कट्टरपंथी संगठनों में शामिल होने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी छवि और नकारात्मक होती है।

2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद, कुछ भारतीय मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लामी शासन की जीत के रूप में देखा। हालांकि, तालिबान के अत्याचारों और उनके द्वारा महिलाओं के अधिकारों के हनन ने भारतीय समाज में भी इस घटना की व्यापक निंदा की। यह घटना भारतीय मुसलमानों के भीतर भी एक बहस को जन्म देती है कि क्या कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराएं इस्लाम की सही प्रतिनिधि हैं।

भारत में इस्लामी रूढ़िवाद और कट्टरपंथी विचारधाराओं ने न केवल भारतीय मुसलमानों की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए भी चुनौतियां पैदा की हैं। कुछ मौलानाओं द्वारा प्रचारित अति-रूढ़िवादी विचारधारा ने मुसलमानों को आधुनिकता, विज्ञान और समाज के मुख्यधारा से दूर करने की प्रवृत्ति बढ़ाई है। इसके साथ ही, आतंकी हमलों, कट्टरपंथी संगठनों के प्रभाव, और वैश्विक इस्लामिक आंदोलनों का असर भारतीय समाज में मुसलमानों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को गहराता है।

भारत में इस्लामी रूढ़िवाद और कट्टरपंथी विचारधाराओं ने न केवल भारतीय मुसलमानों की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए भी चुनौतियां पैदा की हैं। कुछ मौलानाओं द्वारा प्रचारित अति-रूढ़िवादी विचारधारा ने मुसलमानों को आधुनिकता, विज्ञान और समाज के मुख्यधारा से दूर करने की प्रवृत्ति बढ़ाई है।

हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा प्रगतिशील और आधुनिकता का समर्थन करता है। हालांकि मजहबी पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई केवल इस्लामिक समाज की नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है, जिसे सभी समाजों को मिलकर हल करना होगा। नीत्शे और इब्न रश्द जैसे दार्शनिकों ने जिन खतरों की ओर इशारा किया था, वे आज भी प्रासंगिक हैं।

मुसलमानों को अपने मजहब की वास्तविक शिक्षाओं की ओर लौटना होगा और कट्टरपंथी विचारधाराओं को अस्वीकार करना होगा। इसके लिए मुस्लिम समाज के भीतर से ही आवाजें उठनी चाहिए, जो तार्किकता, विज्ञान और ज्ञान के आधार पर समाज का निर्माण करें। इसके अलावा, इस्लामी शिक्षाओं की सही व्याख्या और प्रसार के लिए शिक्षित मौलानाओं और मजहबी नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वैश्विक शांति और मुस्लिम समुदाय की सकारात्मक छवि को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि मुस्लिम समाज आंतरिक सुधारों पर जोर दे, और अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जागरूकता फैलाए।

ईरान का जुआ
अरबों का नुकसान, खतरे में सरकार

पीटर बाउम

मेरे अधिकतर रिटायरमेंट के बाद के समय को राजनीतिक शोध और इज़राइल समर्थक सक्रियता में समर्पित करने से पहले, मैंने अंतरराष्ट्रीय वित्त की दुनिया में एक सफल करियर बिताया था, पहले एक वैश्विक बैंक में ऑडिटर के रूप में, फिर यूरोबॉन्ड ट्रेडर के रूप में और अंत में फंड मैनेजर के रूप में। 18 वर्ष की आयु से ही मुझे दुनिया भर में यात्रा करने और एशिया और मध्य पूर्व में व्यापक रूप से काम करने का अवसर मिला। मैंने अपने कई पुराने सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखा, विशेष रूप से मुस्लिम देशों में। मुझे मिस्र और जापान में लंबे समय तक काम करने का वास्तविक आनंद प्राप्त हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया (और सिंगापुर) में कम, और इससे मेरी ट्रेडिंग और निवेश करियर के लिए ग्राहक सूची बनाने में मदद मिली।

हालाँकि, जो निवेश मैंने किया और जिनके लिए मैंने सलाह दी, वे ईरानी ग्राहक आधार के लिए वित्तीय दृष्टि से लाभकारी साबित हुए, बिल्कुल इसके विपरीत, जो निवेश ईरानी सरकार ने खुद किए थे, वे लगभग सभी विफल हो गए हैं, या पूरी तरह से समाप्त होने की

ईरान अब आर्थिक रूप से टूट चुका है, सीरिया में असद को समर्थन देने वाले निवेश खत्म हो गए हैं, क्योंकि शासन के पतन के बाद इज़राइल ने सभी सीरियाई हथियारों को नष्ट कर दिया।

प्रक्रिया में हैं। विफल निवेश व्यापारिक जीवन का हिस्सा होते हैं, जैसे दक्षिण सागर बुलबुला, वॉल स्ट्रीट क्रैश, संपत्ति संकट, माडॉफ घोटाला और सब-प्राइम बांड बाजार, जिनके कारण कई संस्थानों का पतन हुआ और इसके बाद ट्रिलियन डॉलर के बैंक बेल-आउट का संकट पैदा हुआ। निवेशक अपनी प्रवृत्तियों, भावनाओं, ज्ञान, सलाह या विश्लेषण के आधार पर उम्मीद करते हैं कि उनके निवेश उन्हें लाभ देंगे। ईरान के अधिनायकवादी धर्मनायकों ने भी इसी तरह के निवेश किए, और ये सभी बहुत कम समय में विफल हो गए, हालांकि उन्होंने अपने जोखिम को फैलाने के लिए एक स्थापित निवेश मानदंड का पालन किया।

ईरान ने लेबनान, सीरिया, यमन और तथाकथित फिलीस्तीनी क्षेत्रों में बड़े वित्तीय निवेश किए। उन्होंने प्रॉक्सी सेनाओं को हथियार, मानव संसाधन, खुफिया जानकारी और धन प्रदान किया। ईरानी फंड मैनेजर थे, और किए गए निवेश में से कुछ चयनात्मक थे, जहाँ प्रॉक्सी स्वतंत्र रूप से काम करते थे, और कुछ अनिवार्य थे, जहाँ निवेशक को यह तय करने का अधिकार था कि किसमें और कैसे निवेश किया जाए।

सालों की सावधानीपूर्वक निवेश योजना, विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, भावनात्मक समझ और अरबों डॉलर के पूंजी निवेश के बावजूद, ये सभी नीतिगत और सैन्य निर्णयों की गलतियों का परिणामस्वरूप समाप्त हो गए, और कार्यों को निभाने के लिए अक्षमतापूर्ण अभिनेता चुने गए। इसका आर्थिक रूप से परिणाम भयावह रहा है, और सैन्य और भू-राजनीतिक शक्ति की हानि ने ईरानी शासन के अंतिम लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। ईरानी रियाल अब गिरावट पर है - आधिकारिक रूप से वर्तमान में डॉलर के मुकाबले 40,000 रियाल है, लेकिन ब्लैक मार्केट में रियाल की कीमत 700,000 प्रति डॉलर है, और इस स्तर पर व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा मिल सकती है।

ईरान अब आर्थिक रूप से टूट चुका है। उनके सीरिया में हत्यारे असद को समर्थन देने वाले निवेश खत्म हो गए हैं, क्योंकि शासन के पतन के बाद इज़राइल ने सभी सीरियाई विमानों, नौसेना, और आधुनिक रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया। लेबनान में हिज़बुल्लाह की हार और गाज़ा में हमास का विनाश भी वर्षों के ईरानी निवेश को नष्ट कर चुका है, चाहे वह राजनीतिक हो या वित्तीय। हूती अपने ईरानी मालिकों को लाल सागर के माध्यम से विश्व शिपिंग को रोककर समर्थन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य चुनौती के साथ-साथ महीनों की बाइबिल जैसी बाढ़ ने यमन की अवसंरचना और कृषि को नष्ट कर दिया है, जिससे ईरान की यमनी शक्ति में भारी बाधा आई है। और यह सब 18 महीनों के भीतर हुआ है, जबकि इसके लिए बीस साल और उससे अधिक की सावधानीपूर्वक विश्लेषणात्मक योजना की आवश्यकता थी।

जैसा कि किसी भी निवेश में होता है, निवेश ऊपर या नीचे जा सकते हैं, और ईरानी संपत्तियाँ एक तेज गिरावट की दिशा में हैं। जब जनवरी 20, 2025 को राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आएंगे, तो ईरान के भीतर और अधिक दबाव बढ़ेगा। घरेलू ताकतें शायद वह कारक बन सकती हैं जो पागल मुल्लाओं की हार को सुनिश्चित करेंगी। अब कौन ईरान में निवेश करेगा? केवल मूर्ख ही इसमें कूदेंगे।

पीटर बाउम, संपादक (अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामले) ब्लिट्ज के लिए एक शोध-छात्र हैं, जो इज़राइल, होलोकॉस्ट, सियोनिज़म, मध्य पूर्व, यहूदी विरोध और अन्य मुद्दों पर विस्तार से लिखते हैं। पीटर बाउम ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में चार दशकों तक काम किया है और पूंजी बाजार में विशेषज्ञता प्राप्त की है।

क्या चीन 2025? तक आर्थिक स्थिरता से निकल पाएगा बाहर?

चीन ने निरंतर आर्थिक बदहाली और ट्रम्प के टैरिफ के बढ़ते खतरे के बीच उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए अधिक आर्थिक प्रोत्साहन की योजना की रूपरेखा तैयार की है।

युचेन ली

चीन की शीर्ष वार्षिक आर्थिक बैठक पिछले महीने संपन्न हुई, जिसमें नेता शी जिनपिंग ने विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक और वित्तीय नीतियों की घोषणा की, जिसमें ब्याज दरों में कटौती और अधिक सरकारी उधारी की दिशा में कदम उठाने की बात कही। पिछले कुछ वर्षों में चीन आर्थिक मंदी और घरेलू उपभोक्ता मांग की कमजोरी से जूझ रहा है, जिसका एक कारण रियल एस्टेट बाजार का पतन है, जहाँ कई मध्यम वर्गीय चीनी नागरिकों ने अपनी संपत्ति निवेश की थी। गोल्डमैन सैक्स के शोध के अनुसार, 2024 में चीन की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 4.9% से घटकर 2025 में 4.5% होने का अनुमान है।

शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अगले साल के लिए 'अधिक सक्रिय' वित्तीय नीति और 'मध्यम रूप से ढीली' मौद्रिक नीति अपनाने की योजना बना रहा है। न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक एशिया सोसाइटी में चीनी अर्थव्यवस्था की विशेषज्ञ

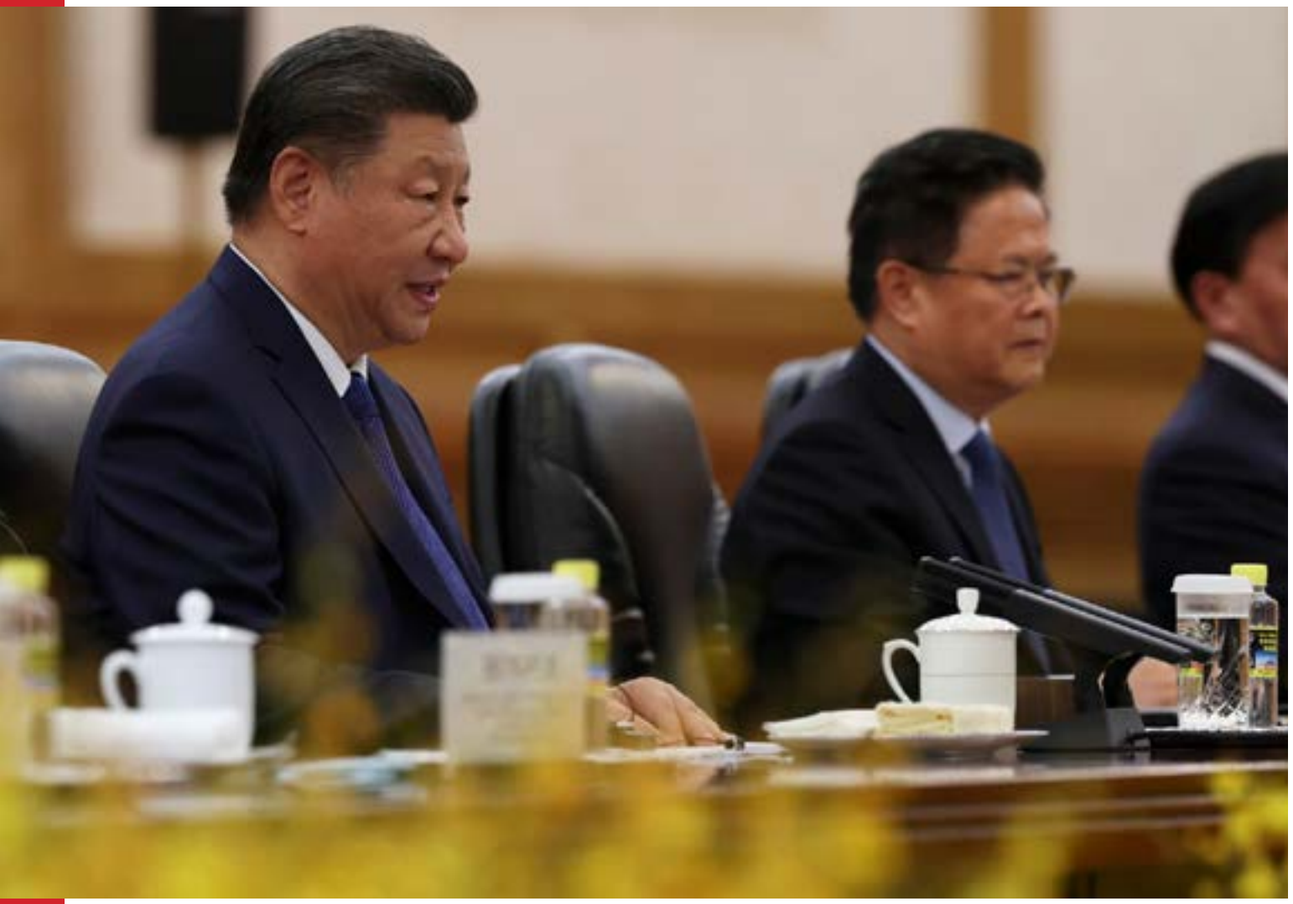

लिज़ी सी. ली ने बताया कि इस साल की 'सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस' ने 'असामान्य रूप से तत्काल' संकेत दिया है।

चीन की विकास रणनीति

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी जिनपिंग ने सम्मेलन में जोर देकर कहा कि अगले साल के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य 'उपभोग को बढ़ावा देना, निवेश दक्षता में सुधार करना और घरेलू मांग को व्यापक रूप से बढ़ाना' है। इसके अलावा, अधिकारियों ने 'राजकोषीय घाटे की दर को बढ़ाने, अल्ट्रा-लंबी अवधि के विशेष सरकारी बांड जारी करने' और मौद्रिक नीति को मध्यम रूप से ढीला करने की योजना बनाई है ताकि तरलता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व आवश्यकताओं और ब्याज दरों को कम किया जा सके।

यह चीन की मौद्रिक नीति में एक बड़ा बदलाव है। 2010 के अंत के बाद से, बीजिंग ने आर्थिक नीति पर तथाकथित 'सावधानीपूर्वक' दृष्टिकोण को अपनाया है। ताइवान के चुंग-हुआ इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक रिसर्च के विद्वान वांग गुओचेन ने डीडब्ल्यू को बताया कि ढील का मतलब है कि अधिकारी अगले साल से बड़े पैमाने पर सरकारी बांड खरीदते हुए अधिक पैसा छापना शुरू करेंगे।

सितंबर में, चीन के पीपुल्स बैंक ने कोविड-19 महामारी के बाद से सबसे बड़े आर्थिक प्रोत्साहन उपायों को लागू किया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1 ट्रिलियन युआन जारी किए गए। नवंबर में, वित्त मंत्रालय ने स्थानीय सरकारों पर दबाव कम करने के लिए 10 ट्रिलियन युआन ($1.4 ट्रिलियन) का ऋण वित्तपोषण योजना शुरू की।

एशिया सोसाइटी की ली ने कहा कि ये उपाय दर्शाते हैं कि चीन की नेतृत्व टीम अधिक करने के लिए तैयार है, लेकिन 'वास्तविक परीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि बीजिंग वास्तव में कितने बड़े पैमाने पर इन योजनाओं को लागू करता है।' वांग ने यह भी चेतावनी दी कि हाल के वर्षों में चीन 'तरलता जाल' में फंस चुका है। मौद्रिक नीति में ढील और ब्याज दरों में कमी के बावजूद लोग भविष्य को लेकर निराशावादी हैं, इसलिए वे खर्च करने के बजाय बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं।

रियल एस्टेट बाजार विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण जबकि आर्थिक बैठकों ने अगले साल के लिए दिशा तय की है, वास्तविक विकास लक्ष्य और विशिष्ट दिशानिर्देश केवल अगले वसंत में औपचारिक संसदीय बैठक के बाद ही घोषित किए जाएंगे। बीजिंग ने 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य 5% निर्धारित किया है। पहले तीन तिमाहियों के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, इस लक्ष्य को हासिल करना इस वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिर भी, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चीनी सरकार 2025 के लिए भी यही लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।

आर्थिक बैठकों में, बीजिंग ने अगले साल 'रियल एस्टेट और शेयर बाजारों को स्थिर करने' और 'रियल एस्टेट बाजार को स्थिर करने के प्रयास जारी रखने' का वादा किया। हालांकि, वांग का मानना है कि रियल एस्टेट बाजार को स्थिर करने की कुंजी चीनी सरकार द्वारा स्थानीय आवास सूची खरीदने में निहित है। ऐसा करके, 'कम से कम सभी को महसूस होगा कि रियल एस्टेट संकट का निचला स्तर आ चुका है,' और यह बाजार में विश्वास बहाल कर सकता है।

बीजिंग 'ट्रम्प के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए एक उपकरण किट' तैयार कर रहा है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी आयातों पर कम से कम 60% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वांग ने कहा कि उनके संस्थान ने लगभग 13 संस्थागत निवेशकों से अनुमान प्राप्त किए हैं, जो बताते हैं कि यदि अमेरिका द्वारा 60% टैरिफ लगाया जाता है, तो चीन की आर्थिक वृद्धि दर 3% तक गिर सकती है, जबकि पहले इसका अनुमान 4.5% था। गोल्डमैन सैक्स के शोध से पता चलता है कि ट्रंप प्रभावी टैरिफ दर में 20 प्रतिशत अंकों की वृद्धि करेंगे, जिससे '2025 में चीन की वास्तविक जीडीपी पर 0.7 प्रतिशत अंकों का असर पड़ेगा।'

हालांकि चीन के शीर्ष नेतृत्व ने सम्मेलन के दौरान अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि 'वर्तमान बाहरी वातावरण में बदलाव से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव गहरे होते जा रहे हैं।' ट्रंप द्वारा संभावित टैरिफ वृद्धि के जवाब में बीजिंग की वर्तमान स्थिति 'सतर्क तैयारी' की है न कि सीधी टकराव की।

वांग ने कहा कि सेमीकंडक्टर में तकनीकी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, जबकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इन उद्योगों को प्राथमिकता देने से सेवा क्षेत्र की वृद्धि बाधित हो सकती है।

गुकेश शतरंज का नया सम्राट

डॉ. आर के सिन्हा

सारा भारत आज के दिन डी. गुकेश के विश्व शतरंज चैंपियन बनने से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गुकेश ने एक नया इतिहास रच दिया है। वे सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने अपने अद्भुत प्रदर्शन से पूरे भारत का मान बढ़ाया है। उनकी इतनी शानदार सफलता में उनकी असाधारण प्रतिभा, समर्पण और रणनीतिक दृष्टिकोण अहम रहे। गुकेश ने बहुत कम उम्र में शतरंज खेलना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें खेल की बारीकियों को समझने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने का पर्याप्त समय मिला। उनमें जन्मजात प्रतिभा है और उनकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत तेज है, जिससे वे जटिल शतरंज रणनीतियों को आसानी से समझ पाते हैं। उन्होंने शतरंज के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया है और लगातार अभ्यास करके अपनी क्षमताओं को निखारा है।

गुकेश को अनुभवी और कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने उनकी खेल तकनीकों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच मिली, जिससे उन्हें विश्व स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली। गुकेश के प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग शामिल था, जिससे उनकी खेल रणनीति का विश्लेषण करना और सुधार करना आसान हो गया।

रणनीतिक गहराई

गुकेश के पास शतरंज में गहरी रणनीतिक सोच है, जो उन्हें खेल के दौरान तत्काल सही निर्णय लेने में मदद करती है। वे दबाव की स्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। उनमें मानसिक रूप से मजबूत होने की क्षमता है, जिससे वे हार से निराश नहीं होते और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं।

गुकेश नियमित रूप से शतरंज का अभ्यास करते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने पिछले मैचों का विश्लेषण करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, जिससे उनकी खेल रणनीति में लगातार सुधार होता रहता है। वे शतरंज के महान खिलाड़ियों के खेलों का लगातार गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करते रहते हैं और उनसे नई तकनीकों को सीखते हैं। गुकेश ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जिससे उन्हें उच्च स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव मिला है।

उन्होंने अलग-अलग शैली के खिलाड़ियों का सामना किया है, जिससे उनकी खेल में विविधता आई है और उन्हें विभिन्न स्थितियों के लिए तैयार किया गया है। गुकेश को अपने परिवार से भरपूर समर्थन और प्रेरणा मिली है, जो उनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक है।

उनके परिवार ने उनके संघर्षों के दौरान उनका भावनात्मक रूप से समर्थन किया और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इन सभी कारणों के संयोजन ने गुकेश को विश्व शतरंज चैंपियन बनने में मदद की है। उनकी सफलता न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह भारत में शतरंज के विकास और प्रोत्साहन का भी प्रतीक है।

इस बीच, कुछ जानकार गुकेश और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद की तुलना भी रहे कर रहे हैं। गुकेश और विश्वनाथन आनंद, दोनों ही भारतीय शतरंज के महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी शैलियों, दृष्टिकोण और खेल में कुछ समानताएं और कुछ मौलिक अंतर भी हैं। दोनों ही खिलाड़ियों में शतरंज की असाधारण प्रतिभा है। वे जटिल स्थितियों को समझने और सटीक चाल चलने में माहिर हैं।

दोनों ही खिलाड़ी अपनी रणनीतिक गहराई के लिए जाने जाते हैं। वे न केवल तात्कालिक लाभ पर ध्यान देते हैं, बल्कि लंबी अवधि की योजनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों में दृढ़ संकल्प है और वे कभी भी हार नहीं मानते हैं। उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से वापसी की है और जीत हासिल की है।

दोनों ही खिलाड़ी अपनी शालीनता और खेल भावना के लिए जाने जाते हैं। वे हारने पर भी सम्मान बनाए रखते हैं। विश्वनाथन आनंद एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जो 90 के दशक से खेल रहे हैं, जबकि गुकेश एक युवा और उभरते हुए खिलाड़ी हैं। आनंद ने कंप्यूटर युग से पहले शतरंज खेला, जबकि गुकेश का विकास कंप्यूटर के युग में हुआ है।

आनंद अपनी तेज और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जबकि गुकेश एक अधिक रणनीतिक और रक्षात्मक खिलाड़ी हैं। आनंद त्वरित चालों और जटिलताओं में माहिर हैं, जबकि गुकेश स्थिति को नियंत्रित करने और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

जाहिर है, आनंद के पास खेल का अधिक अनुभव है और उन्होंने कई विश्व चैंपियनशिप जीती हैं, जबकि गुकेश अभी भी अपने करियर के शुरुआती चरण में हैं। आनंद ने दशकों तक शीर्ष स्तर पर खेला है, जबकि गुकेश अभी भी वैश्विक शतरंज समुदाय में अपनी जगह बना रहे हैं।

आनंद एक अधिक सहज और रचनात्मक खिलाड़ी हैं, जबकि गुकेश अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक खिलाड़ी हैं। आनंद स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर खेलते हैं, जबकि गुकेश अपनी तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारत में शतरंज पहले से ही काफी लोकप्रिय है, लेकिन गुकेश जैसे युवा खिलाड़ियों के उदय से यह और भी लोकप्रिय हो सकता है।गुकेश जैसे युवा खिलाड़ियों की सफलता से युवा पीढ़ी को शतरंज में रुचि लेने की प्रेरणा मिलेगी। युवाओं के लिए एक आदर्श मॉडल होने से अधिक युवा शतरंज खेलने के लिए आकर्षित होंगे।

ऑनलाइन शतरंज प्लेटफॉर्म और कंप्यूटर विश्लेषण उपकरणों की उपलब्धता से खेल अधिक सुलभ हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से सीखने और खेलने के विकल्पों ने शतरंज को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। शतरंज को अब पहले से अधिक मीडिया कवरेज मिल रहा है, जिससे खेल के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। प्रमुख समाचार चैनलों और खेल वेबसाइटों पर शतरंज की घटनाओं को कवर किया जा रहा है।

शतरंज को अब स्कूलों में एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में मान्यता दी जा रही है, जिससे बच्चों को खेल के लाभों का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने से आने वाली पीढ़ी के लिए इसे और लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

शतरंज में प्रायोजन में वृद्धि से खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। प्रायोजकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने से खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

गुकेश का विश्व चैंपियन बनना भारत में शतरंज को और लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया जाएगा और शतरंज में करियर बनाने के लिए एक नया रास्ता खुलेगा।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

2025 महाकुंभ

आध्यात्मिक उर्मि की ओर

सचिदानंद पाण्डेय

प्रयागराज, जो कि गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, एक बार फिर से अपने भव्यतम और पवित्रतम धार्मिक आयोजन, महा कुंभ 2025 की तैयारी में जुटा है। यह आयोजन न केवल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, बल्कि इसे आध्यात्मिकता और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का वैश्विक संगम भी कहा जाता है। महा कुंभ, जहां धर्म और आस्था के साथ-साथ भक्ति और कर्मकांड का अद्वितीय मेल होता है, एक ऐसा अवसर होता है जब लोग अपने जीवन के पापों से मुक्त होने के लिए इस महायात्रा में शामिल होते हैं।

आध्यात्मिक संगम की महिमा

कुंभ मेला का महत्व वेदों और पुराणों में वर्णित है, जहां इसे आत्म-शुद्धि और मुक्ति का प्रमुख अवसर माना गया है। सनातन धर्म की धारा में कुंभ वह समय होता है जब पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है, और गंगा स्नान के माध्यम से भक्तगण अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। मान्यता है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से जीवन की समस्त बाधाओं और कष्टों का निवारण होता है। महा कुंभ 2025, जहां करोड़ों लोग एकत्र होंगे, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि विश्व में आस्था का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी है।

प्रयागराज में तैयारियां: एक भव्य आध्यात्मिक यज्ञ

उत्तर प्रदेश सरकार ने महा कुंभ 2025 के लिए व्यापक तैयारियों की योजना बनाई है, ताकि इस विशाल आयोजन को कुशलता से संपन्न किया जा सके। लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कुंभ नगरी की स्थापना की जा रही है, जहां पर अस्थायी आवास, सड़कें, बिजली, पानी की आपूर्ति और संचार सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं के साथ-साथ संगम क्षेत्र में 11 अस्थायी अस्पताल और 150,000 से अधिक अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

इस कुंभ को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए 20,000 से अधिक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जो न केवल सफाई का ध्यान रख रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथ ही, 500 गंगा प्रहरी नियुक्त किए गए हैं, जो गंगा नदी की पवित्रता और स्वच्छता का पालन सुनिश्चित करेंगे। यह प्रयास कुंभ मेले को एक पर्यावरण-संवेदनशील आयोजन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में धर्म और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

तकनीकी स्पर्श और आधुनिक सुविधाएं

आधुनिक युग की तकनीक ने भी इस महायज्ञ में अपनी भूमिका निभाई है। महा कुंभ 2025 के आयोजन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है ताकि इस आयोजन को सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक बनाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट्स और रियल-टाइम सूचना प्रणाली के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनकी यात्रा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। मोबाइल एप्स और डिजिटल सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों को आवास, यातायात, और अन्य सुविधाओं की जानकारी समय पर मिल सके।

योगी आदित्यनाथ का विजनः

आध्यात्मिक चमत्कार होगा महाकुंभ 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के सफल और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर जोर देते हुए, उन्होंने सड़कों, पुलों और स्वच्छता सुविधाओं सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की देखरेख की है। इसके अतिरिक्त, सरकार बेहतर भीड़ प्रबंधन और मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक समय के अपडेट के लिए डिजिटल सेवाओं को बढ़ा रही है। एक निर्बाध आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए आयोजन की पवित्रता को बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ-साथ परिवहन, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

इस बार के कुंभ मेले में सुरक्षा के भी अत्यधिक ध्यान रखा जा रहा है। 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, जो भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की देखरेख करेंगे। 2,500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे आयोजन स्थल की निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी अनहोनी घटना को रोका जा सके। इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी भय के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकें और इस अद्वितीय आयोजन का हिस्सा बन सकें।

विश्वभर से आस्था का संगम

महा कुंभ 2025, केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बनने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी इस आयोजन में शामिल होंगे। कुंभ का संदेश विश्वभर में प्रेम, एकता, और आध्यात्मिकता का प्रचार करता है। इस विशाल आयोजन में विविध भाषाओं, संस्कृतियों, और धार्मिक परंपराओं का संगम देखने को मिलता है, जहां लोग जाति, धर्म, और भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक ही ध्येय के साथ संगम स्नान करने आते हैं – आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति।

कुंभ की आस्था और भारतीय राजनीति

कुंभ जैसे विशाल आयोजनों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव असीमित होता है। यह आयोजन भारत की राजनीति और राष्ट्रीय चेतना पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों और सुविधाओं के माध्यम से न केवल आयोजन की सफलता सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि इससे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की भी एक अनूठी पहचान विश्व मंच पर स्थापित हो रही है। कुंभ मेला, जहां धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का मेला है, वहीं यह आयोजन सामाजिक सद्भाव, एकता और सेवा के मूल्यों को भी प्रकट करता है।

सारांश

महा कुंभ 2025 की तैयारी न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की दिशा में प्रयास है, बल्कि यह मानवता की शक्ति, आस्था और आध्यात्मिकता का महायज्ञ है। यह आयोजन विश्वभर में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बनेगा। करोड़ों श्रद्धालु जब गंगा के पवित्र जल में स्नान करेंगे, तब वे केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का अनुभव करेंगे। महा कुंभ एक ऐसा अवसर है जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं ही हमारी असली धरोहर हैं, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और मूल्यों से जोड़ती हैं। प्रयागराज एक बार फिर से अपने उन आदर्शों को साकार करने जा रहा है, जो सदियों से आस्था और भक्ति की आधारशिला रहे हैं। महा कुंभ 2025 के दौरान, यह पवित्र भूमि उन तमाम भक्तों का स्वागत करेगी जो अपने जीवन के पापों को धोने और मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने के लिए यहां आएंगे। यह आध्यात्मिक महासागर, जो भक्तों के मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करेगा, विश्वभर में प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश भी फैलाएगा।

महा कुंभ मेला 2025: आयोजन तिथियाँ और शाही स्नान विवरण

महा कुंभ मेला 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण स्नान तिथियाँ, जिन्हें 'शाही स्नान' कहा जाता है, मनाई जाती हैं। ये तिथियाँ विशेष रूप से पुण्यकारी मानी जाती हैं, और इन दिनों लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुन और सरस्वती के संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने का विश्वास करते हैं।

यहाँ 2025 के महा कुंभ मेला के प्रमुख स्नान तिथियाँ दी जा रही हैं:

पौष पूर्णिमा:	13 जनवरी 2025
मकर संक्रांति:	14 जनवरी 2025
मौनी अमावस्या:	29 जनवरी 2025
बसंत पंचमी:	03 फरवरी 2025
अचला सप्तमी:	04 फरवरी 2025
माघ पूर्णिमा:	12 फरवरी 2025
महाशिवरात्रि:	26 फरवरी 2025

इन तिथियों पर विशेष स्नान, पूजा-अर्चना और धार्मिक-आध्यात्मिक आयोजन होंगे। यह अवसर श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा।

एक शाश्वत लय

ज़ाकिर हुसैन का तबला और ब्रह्मांड की धड़कन

संदीप कुमार

उनका सफर मध्य दिसंबर में सैन फ्रांसिस्को में समाप्त हुआ, जहां वे एक दुर्लभ फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन उनका धरोहर... उनका संगीत... हमेशा जीवित रहेगा, करोड़ों दिलों में गूंजता रहेगा। उस्ताद जाकिर हुसैन के जाने से भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है। उनका तबला सिर्फ़ एक वाद्य नहीं था; यह उनकी आत्मा का विस्तार था। हर ताल, हर स्ट्रोक में सदियों पुरानी परंपरा की समृद्धि झलकती थी, और इसे उन्होंने एक आधुनिक जीवंतता के साथ जोड़ा जो सीमाओं से परे थी। उस्ताद अल्ला रक्खा के वंश में जन्मे, जाकिर हुसैन की महारत सिर्फ़ तबला वादन में निरंतरता ही नहीं थी – वास्तव में, शास्त्रीय संगीत का एक पुनर्जागरण था।

हुसैन के हाथ तबले पर जब नाचते थे, तब ऐसी लय सृजित होती थी, जो श्रोता की आत्मा से सीधे संवाद करती थी। जॉर्ज हैरिसन और जॉन मैकलॉघलिन जैसे दिग्गजों सहित अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ उनके सहयोग ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जैज़, रॉक और विश्व संगीत के साथ मिलाकर पूर्व और पश्चिम को एक तार में जोड़ने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। यह फ्यूजन महज़ प्रयोग नहीं था - यह संस्कृतियों के बीच दिल से किया गया संवाद था, जहाँ तबला सार्वभौमिक सद्भाव की आवाज़ था। फिर भी, वैश्विक प्रसिद्धि के बीच, वे शास्त्रीय संगीत के सच्चे संरक्षक बने रहे। शांत, मंद रोशनी वाले हॉल में उनके प्रदर्शन ने कालातीत राग परंपराओं को जगाया, क्योंकि उनका तबला तानपुरा और सितार के साथ इस तरह से संवाद करता था कि दर्शक तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इन प्रदर्शनों में एक अंतरंगता थी, जैसे कि उनके द्वारा बजायी गई प्रत्येक ताल ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित हो रही हो, जो प्राचीन और शाश्वत दोनों को बुला रही हो। उनकी उपस्थिति चुंबकीय थी - न केवल उनकी विलक्षण प्रतिभा के लिए, बल्कि उसके साथ जुड़ी विनम्रता के लिए भी। उनकी आंखों में चमक, शरारती मुस्कान जो तब दिखाई देती थी जब वे विशेष रूप से जटिल लय बजाते थे, उन्हें लाखों लोग पसंद करते थे, वे लाखों संगीत प्रेमियों के चहते थे। वह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संगीत को तो गंभीरता से लिया, लेकिन कभी खुद को नहीं।

जाकिर हुसैन ने जो कुछ पीछे छोड़ा है वह रिकॉर्डिंग या प्रदर्शन से कहीं अधिक है; यह गहन संगीत संवाद की विरासत है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे है भले ही अब उनके हाथ तबला की शोभा न बढ़ा सकें, वह चीर-परिचीत लय कानों में मिसरी न घोल सके, लेकिन उनका यादें सदैव जेहन में रहेगा, संगीत के हृदय में एक शाश्वत लय बनी रहेगी।

आर्कटिक की जंग

नई वैश्विक टकराव की भूमि

चूंकि वैश्विक शक्तियां विशाल संसाधनों और रणनीतिक मार्गों पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए चीन और भारत भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए उत्सुक हैं।

एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (सेवानिवृत्त)

आर्कटिक क्षेत्र, जो अब भी काफी हद तक अनछुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से तेल, गैस और समुद्री जीवन के लिए। इसे ऐतिहासिक रूप से महान शक्तियों के बीच संघर्ष का संभावित केंद्र माना जाता है।

रूस ने लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना प्रभावशाली प्रभुत्व बनाए रखा है। हालांकि, नाटो के उत्तरी विस्तार ने मॉस्को को अपने सैन्य प्रभाव को यहां और अधिक मजबूत करने के लिए मजबूर किया है।

बढ़ती हुई महाशक्ति चीन ने भी आर्कटिक मामलों में अपनी रुचि बढ़ाई है, जबकि भारत, अपनी भौगोलिक दूरी के बावजूद, इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है।

अमेरिका के साथ चीन और रूस के बढ़ते टकराव ने इन दोनों शक्तियों को आर्कटिक मामलों में अधिक सहयोग और समन्वय की ओर अग्रसर किया है।

धरती के कुल भूभाग के छठे हिस्से से अधिक पर फैला हुआ आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव को घेरता है और विशाल तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों से ढका है, जिनकी मोटाई 20 मीटर तक पहुंच सकती है। अनुमान है कि यहां विश्व के अज्ञात तेल और प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 22% हिस्सा है, जिसमें रूस के पास आर्कटिक के कुल ऊर्जा संसाधनों का 52% है और नॉर्वे के पास 12%।

वैश्विक औद्योगिकीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण तापमान बढ़ा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 2024 में आर्कटिक समुद्री बर्फ का न्यूनतम विस्तार 4.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर दर्ज किया

गया था, जो दीर्घकालिक औसत से लगभग 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर कम है। समुद्री बर्फ के घटने की दर लगभग 13% प्रति दशक है, जिससे अनुमान है कि 2040 तक आर्कटिक गर्मियों में बर्फ रहित हो सकता है।

बर्फ के पिघलने के परिणाम गंभीर हैं, जो समुद्र के स्तर को बढ़ा सकते हैं और कई द्वीपीय क्षेत्रों और तटीय शहरों को खतरे में डाल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिसे हाल ही में बाकू, अजरबैजान में COP29 जैसे मंचों पर उजागर किया गया है।

अंटार्कटिका के विपरीत, जहां 1959 की संधि केवल शांतिपूर्ण गतिविधियों की अनुमति देती है, आर्कटिक के लिए ऐसी कोई संधि नहीं है। 1996 में स्थापित आर्कटिक परिषद आर्कटिक राष्ट्रों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस शामिल हैं। पर्यवेक्षक देशों को आर्कटिक राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्राधिकार को स्वीकार करना चाहिए, जबकि आर्कटिक महासागर पर व्यापक कानूनी ढांचे को भी मान्यता देनी चाहिए। मई 2013 में भारत आर्कटिक परिषद का स्थायी पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त करने वाला 11वां देश बना।

रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से आर्कटिक में सैन्य ठिकानों और निगरानी प्रणालियों का संचालन किया है, जिसमें परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भी शामिल है।

रूस ने इस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से संचालित आइसब्रेकर्स (बर्फ तोड़ने वाले जहाज) का संचालन किया है। हालांकि रूस,

अमेरिका और नॉर्वे के बीच आर्कटिक मिलिटरी एनवायरनमेंटल कोऑपरेशन (AMEC) समझौते ने कुछ सोवियत और अमेरिकी संपत्तियों को हटाने में मदद की, लेकिन अतिरिक्त देशों की बढ़ती रुचि ने इन दो प्रमुख शक्तियों के बीच एक नए शीत युद्ध के गतिशीलता को जन्म दिया है।

यूक्रेन के 2014 से लेकर अब तक के हालात के मद्देनजर पैदा हुए भू-राजनीतिक तनावों के कारण जो सहयोगात्मक वातावरण एक समय मौजूद था, वह अब ख़त्म हो चुका है।

आर्कटिक समुद्री मार्ग

बर्फ के अधिक पिघलने से आर्कटिक क्षेत्र गर्मी के महीनों में लंबे समय तक खुला रहने लगा है। 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक नौवहन उद्योग में क्रांति लाने वाले तीन मुख्य मार्ग हैं।

उत्तरी सागर मार्ग (NSR) रूस के आर्कटिक तट के साथ स्थित है। यहां सबसे पहले बर्फ पिघलती है, इसलिए यह अधिक समय तक उपलब्ध रहता है। यह मार्ग सबसे अधिक वाणिज्यिक क्षमता वाला है: यह पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच समुद्री दूरी को 21,000 किलोमीटर से घटाकर 12,800 किलोमीटर कर देता है। यह 10-15 दिनों की ट्रांजिट समय की बचत करता है। सोवियत युग के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और परिवहन के लिए इस मार्ग का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।

2009 में, दो जर्मन जहाजों ने एक रूसी आइसब्रेकर के नेतृत्व में NSR के माध्यम से दक्षिण कोरिया के बुसान से नीदरलैंड के

रॉटरडैम तक की पहली व्यावसायिक यात्रा की, जिससे इस मार्ग की वाणिज्यिक संभावनाओं का साक्षात्कार हुआ।

दूसरा मार्ग नॉर्थ वेस्ट पैसेज (NWP) है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच कनाडा के आर्कटिक द्वीपसमूह से होकर गुजरता है, जिसका पहली बार उपयोग 2007 में किया गया था। यह मार्ग जल्द ही अधिक नियमित उपयोग के लिए खुल सकता है।

तीसरा संभावित ट्रांसपोलर सी रूट (TSR) है, जो आर्कटिक के केंद्रीय भाग का उपयोग कर बेरिंग जलडमरूमध्य और अटलांटिक महासागर के मुरमान्स्क बंदरगाह को सीधे जोड़ सकता है। यह मार्ग अभी सैद्धांतिक है और जलवायु परिवर्तन के साथ भविष्य में विकसित हो सकता है।

मॉस्को की रणनीति

रूस आर्कटिक में सबसे बड़ा हितधारक है, यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 10% और सभी रूसी निर्यात का 20% हिस्सा है। आर्कटिक को 2023 के संस्करण में क्रेमलिन की विदेशी नीति अवधारणा में नवीनीकृत महत्व मिला है, जिसमें शांति और स्थिरता के संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों में कमी पर बल दिया गया है।

उत्तरी सागर मार्ग (NSR) का विकास एक प्रमुख उद्देश्य बना हुआ है, जिसमें रूस ने आर्कटिक में अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

रूस की नई आर्कटिक नीति 2035, जिसे 2020 में हस्ताक्षरित किया

गया, उत्तरी सागर मार्ग (NSR) पर रूस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। यह नीति संयुक्त राज्य अमेरिका की नाराज़गी का कारण बनी है, जो NSR को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में देखना चाहता है, ताकि इसके संचालन पर व्यापक 'फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस' (FONOPs) के नियम लागू हो सकें। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि जो जहाज NSR में रूसी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है। रूस की सहयोग की इच्छा के बावजूद, पश्चिमी देश लगातार आर्कटिक से जुड़े मामलों में रूस को खलनायक की तरह प्रस्तुत करते हैं।

एक नया खिलाड़ी

चीन, जो खुद को 'नियरे-आर्कटिक राज्य' मानता है, आर्कटिक में एक प्रमुख भागीदार बनने की कोशिश कर रहा है। जनवरी 2018 में, चीन ने अपनी आधिकारिक आर्कटिक नीति प्रकाशित की, जिसमें आर्कटिक संसाधनों के प्रति अपनी रुचि और अनुसंधान, सैन्य और अन्य उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

भारत का अनुसंधान मुख्य रूप से गतिशीलता, ग्लेशियर, कार्बन पुनर्चक्रण, ग्लेशियोलॉजी, भूविज्ञान, वायुमंडलीय प्रदूषण और अंतरिक्ष मौसम जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

चीन आर्कटिक अनुसंधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक निवेश करता है और शंघाई में एक पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट संचालित करता है। इसके पास अनुसंधान जहाजों का बेड़ा है और दो MV Xue Long आइसब्रेकर भी हैं। इसके अलावा, 2004 में चीन ने आर्कटिक येलो रिवर स्टेशन की स्थापना की। 2018 में, शंघाई स्थित COSCO शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूरोप और चीन के बीच आर्कटिक के माध्यम से आठ परिवहन यात्राएँ कीं।

चीन की 'पोलर सिल्क रोड,' जिसे 2018 में रूस के साथ एक संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया, इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। रूस की तरह, चीन भी आर्कटिक में परमाणु-चालित आइसब्रेकर तैनात करने की योजना बना रहा है, जिससे वह ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। हालांकि, डेनमार्क ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोत्साहन पर, ग्रीनलैंड में एक पुराना सैन्य अड्डा खरीदने और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के चीन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

भारत की दिलचस्पी

एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में भारत, आर्कटिक में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की आकांक्षा रखता है। भारत ने जुलाई 2008 से नॉर्वे के स्वालबार्ड में 'हिमाद्री' नामक स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन संचालित किया है। स्वालबार्ड, जो पृथ्वी पर सबसे उत्तरी स्थान है जहाँ पूरे वर्ष लोग रहते हैं, उत्तरी ध्रुव से लगभग 1,200 किलोमीटर दूर है और इसकी जनसंख्या लगभग 2,200 है।

भारत का अनुसंधान मुख्य रूप से फियोर्ड गतिशीलता, ग्लेशियर, कार्बन पुनर्चक्रण, ग्लेशियोलॉजी, भूविज्ञान, वायुमंडलीय प्रदूषण और अंतरिक्ष मौसम जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। 2014 में, भारत ने कोंग्सफियोर्ड, स्वालबार्ड में 'IndARC' नामक एक पानी के नीचे स्थित वेधशाला की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आर्कटिक मौसम विज्ञान के मापदंडों और दक्षिण-पश्चिम मानसून के बीच संबंधों का पता लगाना था। इसके अलावा, भारत की ONGC विदेश ने रूस की आर्कटिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं में निवेश में रुचि दिखाई है।

मार्च 2022 में, भारत की आर्कटिक नीति, जिसका शीर्षक 'भारत और आर्कटिकः सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण' है, जारी की गई। इस दस्तावेज़ में भारत की रुचियों को दर्शाया गया है, जिसमें आर्थिक और संसाधन संभावनाएँ, समुद्री कनेक्टिविटी, और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करना शामिल है।

आर्कटिक भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह अपनी समुद्री व्यापार मार्गों का विस्तार करके अपनी बढ़ती निर्यात क्षमता के लिए नए बाजारों तक पहुंच बनाने और तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है।

भारत और रूस दोनों ने 7,200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो भारत, ईरान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल को स्थानांतरित कर सकता है, लागत और समय को काफी कम कर सकता है, और चेन्नई-वलादिवोस्तोक कॉरिडोर भी NSR का हिस्सा बन सकता है।

हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि भारत मॉस्को के साथ भारतीय शिपयार्ड में आइसब्रेकर के निर्माण के बारे में चर्चा कर रहा है, जिससे आर्कटिक मामलों में भारत की प्रतिबद्धता और संभावित सहयोग के विस्तार का संकेत मिलता है।

भारत आर्कटिक क्षेत्र में खनन के अवसरों का भी पता लगा सकता है, हालांकि व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय की गहन समुद्री खनन पर रोक लगाने की मांगें जारी हैं। विशेष रूप से, नॉर्वे इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत करने वाला पहला देश बनना चाहता है, जो आर्कटिक परिषद में उसकी सदस्यता और आर्कटिक भू-राजनीति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है।

कनाडा और उत्तरी यूरोपीय देशों का आर्कटिक मामलों में महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने अमेरिका को इन देशों के साथ अपने गठजोड़ को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।

अगला बड़ा खेल

जैसे-जैसे 'अगला बड़ा खेल' सामने आता है, आर्कटिक शोधकर्ताओं को आकर्षित करता जा रहा है। अंटार्कटिका के विपरीत, आर्कटिक राज्यों के पास समुद्री कानून के तहत स्थापित क्षेत्रीय दावे हैं। नतीजतन, आर्कटिक में बड़ी शक्तियों की राजनीति, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में चर्चाएँ रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान तेजी से आकर्षित कर रही हैं।

रूस की उत्तरी नौसेना रणनीतिक रूप से पूरे आर्कटिक में तैनात है और इस क्षेत्र में उसका प्रभावशाली स्थान है। 1867 में रूस से अलास्का की खरीद के बाद अमेरिका एक आर्कटिक राज्य बन गया। कनाडा और उत्तरी यूरोपीय देशों का आर्कटिक मामलों में महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने अमेरिका को इन देशों के साथ अपने गठजोड़ को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।

विशेष रूप से, उत्तरी सागर मार्ग (NSR) लंदन से योकोहामा, जापान के बीच यात्रा करने वाले मालवाहक जहाजों के लिए एक परिवहन मार्ग प्रदान करता है, जो स्वेज नहर की तुलना में 37% छोटा है। रूस अपनी आर्कटिक तटरेखा के साथ मजबूत समर्थन बुनियादी ढांचे के माध्यम से इस लाभ का आर्थिक रूप से लाभ उठाना चाहता है। मॉस्को अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों को अपनी आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा मानता है।

जैसे-जैसे आर्कटिक दौड़ तेज हो रही है, रूस की संसाधन-निर्भर अर्थव्यवस्था इन प्रयासों में आगे बढ़ रही है, जिसने लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर समुद्र तल के अधिकारों को सुरक्षित कर लिया है। इसके अलावा, रूस ने कई सोवियत-युग के सैन्य अड्डों को पुनर्जीवित किया है और अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है, अब वह सात परमाणु-संचालित आइसब्रेकर और लगभग 30 डीजल-संचालित जहाज संचालित करता है। इसके विपरीत, अमेरिका और चीन प्रत्येक केवल दो डीजल-संचालित आइसब्रेकर संचालित करते हैं। नाटो ने भी बरेंट्स सागर और स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं।

चीन आर्कटिक को ऊर्जा और खनिजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखता है, जबकि भारत संघर्ष की बजाय एक सहयोगी क्षेत्रीय दृष्टिकोण की उम्मीद करता है। फिर भी, अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा पहले से ही महत्वपूर्ण परिणाम दिखा रही है।

जबकि अमेरिका वैश्विक महाशक्ति का खिताब रखता है, रूस आर्कटिक में सबसे प्रमुख शक्ति बनकर उभरा है। रूस के साथ मजबूत संबंधों और हाल ही में चार आइसब्रेकर के आदेश के साथ, भारत आर्कटिक मामलों में एक प्रासंगिक भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। भारत को आर्कटिक में सक्रिय रूप से जुड़ा रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी उपस्थिति सिर्फ पर्यवेक्षण तक सीमित न रहे।

एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (सेवानिवृत्त), भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी लड़ाकू परीक्षण पायलट और नई दिल्ली में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के पूर्व महानिदेशक।

(यह लेख सबसे पहले RT न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित हुआ था।)

रूस की अर्थव्यवस्था पुतिन की सबसे बड़ी कमज़ोरी

कठोर प्रतिबंध कर सकते हैं पुतीन को यूक्रेन से बातचीत के लिए मजबूर

थियोडोर बुन्ज़ेल
एवं
एलिना रिबाकोवा

1762 में, सात वर्षों के युद्ध के दौरान, प्रशा के फ्रेडरिक महान की स्थिति अत्यंत गंभीर दिखाई दे रही थी। त्सारवादी रूसी सेना, प्रशा को थका देने के बाद, बर्लिन की ओर बढ़ रही थी और उसे खतरा था। लेकिन फिर अप्रत्याशित घटित हुआः रूस की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, और उनके प्रशा-प्रेमी उत्तराधिकारी, सम्राट पीटर III, ने अचानक रूसी सेना को रोक दिया और शांति की अपील की, यहां तक कि फ्रेडरिक की मदद के लिए रूसी सैनिक भी भेजे। फ्रेडरिक ने इसे 'ब्रांडेनबर्ग के घर का चमत्कार' कहा, जो यह दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक बदलाव और एक नए नेता की व्यक्तिगत सहानुभूति अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को अचानक उलट सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप की निर्णायक जीत अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 'पुतिन के घर का चमत्कार' तो नहीं हो सकती, लेकिन यह क्रेमलिन को यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में एक नया संबल जरूर देती है। ट्रंप अमेरिकी समर्थन को लेकर सशंकित हैं और उन्होंने संघर्ष को खत्म करने का वादा किया है। उनका दावा कि वह '24 घंटों में' युद्ध समाप्त कर देंगे, बेशक एक अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन यह वाशिंगटन में उस बढ़ते विचारधारा का प्रतीक है जो एक समझौते द्वारा समाधान की वकालत करती है।

हालांकि, 1762 की प्रशा के विपरीत, रूस आज कमजोर स्थिति में नहीं है; वास्तव में, उसकी सेना ने मैदान में बढ़त हासिल की है। मॉस्को मानता है कि उसके पास इस समय गति है और वह समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, कीव अभी भी युद्ध में बना हुआ है और समर्पण करने के मूड में नहीं है। ट्रंप की युद्ध समाप्ति की तत्परता को एक स्थायी समाधान में बदलने के लिए पश्चिम को पहले मॉस्को पर दबाव बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ताकि वार्ता की मेज पर उसे संतुलन में लाया जा सके। अन्यथा, रूस के अनुकूल एक जल्दबाज़ी में हुआ संघर्ष विराम सिर्फ एक अस्थायी विराम हो सकता है, जिसके बाद क्रेमलिन अधिक हासिल

करने की कोशिश करेगा।

पश्चिम के लिए सौभाग्य से, रूस के पास एक महत्वपूर्ण कमजोरी हैः उसकी अर्थव्यवस्था। कई पर्यवेक्षकों ने यह गलत धारणा बना ली है कि युद्ध के आरंभ में मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंध काम नहीं कर रहे थे, और उसकी अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है। लेकिन वास्तव में, प्रतिबंधों ने भारी क्षति पहुंचाई है और क्रेमलिन की नीति विकल्पों को सीमित कर दिया है। अब रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के बढ़ते खर्चों से विकृत हो रही है। सैकड़ों हजारों रूसी पुरुष युद्धक्षेत्र में मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं—अक्टूबर में रूस को प्रतिदिन 1,500 सैनिकों का नुकसान हुआ। रक्षा खर्च बजट को निगल रहा है। और यदि मॉस्को की ऊर्जा से होने वाली आय और पश्चिमी निर्मित दोहरे उपयोग वाले सामानों का आयात धीमा हो जाता है, तो उसे आर्थिक और सैन्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिबंधों को और कड़ा करना रूस के युद्ध प्रयास को वित्तीय रूप से अस्थिर बना देगा, और युद्ध मशीन के ठप होने की संभावना और बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों के कारण घरेलू असंतोष के बढ़ते दबाव के चलते, पुतिन यूक्रेन के अधिक अनुकूल शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

वाशिंगटन और उसके यूरोपीय साझेदार तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के शेष हफ्तों का लाभ उठाकर रूस की ऊर्जा आय और प्रौद्योगिकी आयात पर और दबाव डाला जा सकता है। अब जब अमेरिका और यूरोप में तेल की कीमतें और मुद्रास्फीति दरें गिर रही हैं, पश्चिमी सरकारें 2022 की तुलना में रूसी ऊर्जा प्रवाह को बाधित करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकती हैं। और जब ट्रंप पद ग्रहण करेंगे, तो उनकी प्रशासन को इन प्रयासों का स्वागत करना चाहिए और उन्हें और मजबूत करना चाहिए। ऐसा करने से ट्रंप को रूस-यूक्रेन वार्ता में लाभ मिलेगा, अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को लाभ होगा, और यूरोप से राजनीतिक रियायतें मिल सकती हैं—ये सभी ऐसे परिणाम हैं जिन्हें ट्रंप अपनी जीत के रूप में गिन सकते हैं।

नींव में दरारें

फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो पश्चिमी प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की उम्मीदें बहुत अधिक थीं। यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों ने रूस पर व्यापक वित्तीय प्रतिबंध लगाए, जिनमें मॉस्को के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध और दूरगामी निर्यात नियंत्रण शामिल थे। यह एक प्रभावशाली प्रयास था, और बाइडन ने घोषणा की कि प्रतिबंध अंततः रूबल को 'मलबे में बदल देंगे।'

फिर भी 2023 में रूसी अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2024 में भी इसी दर से वृद्धि का अनुमान है। मॉस्को का चालू खाता अधिशेष—जो उसके निर्यात का आयात से अधिक मूल्य है—2024 में $60 बिलियन से अधिक होने की संभावना है, जो 2023 में $50 बिलियन था। बढ़े हुए तेल राजस्व ने उसके बजट घाटे को प्रबंधनीय बना रखा है। रूस ने तीसरे देशों के माध्यम से अपनी सेना के लिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी का स्रोत ढूंढ लिया है और यूरोप से खोए व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चीन और भारत की ओर पुनर्निर्देशित कर दिया है।

लेकिन ये शीर्षक आंकड़े बुनियादी आर्थिक कमजोरियों को छिपाते हैं, जिन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों ने और बढ़ा दिया है। रूस में मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत से अधिक है क्योंकि अर्थव्यवस्था भारी युद्धकालीन खर्च और घटती श्रम आपूर्ति के कारण अत्यधिक गर्म हो रही है, जिससे केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला कारक है नाममात्र वेतन वृद्धि, जो 17 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। बेरोजगारी दर लगभग दो प्रतिशत है—एक अविश्वसनीय रूप से कम संख्या जो वेतन वृद्धि और सेना के बड़े साइन-अप बोनस के साथ मिलकर श्रम की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। नवंबर के अंत में, रूबल अपने दो साल के सबसे निचले स्तर पर गिर गया, जो चढ़ती मुद्रास्फीति और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण कठिन मुद्रा प्रवाह में गिरावट का परिणाम है—मार्च 2022 में $34 बिलियन से घटकर सितंबर 2024 में $2 बिलियन। रूस का बजट भी दबाव में है। क्रेमलिन 2025 में रक्षा खर्च में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत से अधिक के बराबर है; तुलना में, अमेरिकी रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत से भी कम है। अब रक्षा रूस के राज्य बजट का एक तिहाई हिस्सा है और उसके सामाजिक सेवाओं के खर्च से दोगुना है। पिछले साल, मॉस्को ने 2025 में रक्षा खर्च में 21 प्रतिशत की कमी की योजना बनाई थी। यह पलटना दर्शाता है कि रूस अपेक्षा से अधिक सैन्य दबाव में है।

दबाव के बिंदु

इन आर्थिक समस्याओं में कुछ विशिष्ट कमजोरियां हैं जिनका पश्चिमी देश फायदा उठा सकते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा है। तेल और गैस का निर्यात रूसी सरकारी राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाता है, और इनसे मिलने वाले राजस्व ने रूस की बजट की कमी को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है। 2022 के अंत में G-7 देशों द्वारा लगाए गए तेल मूल्य कैप के बावजूद, रूस ने इस अंतर को कम करने में सफलता पाई है। रूसी तेल और वैश्विक कच्चे तेल के बीच का मूल्य अंतर $30 प्रति बैरल से घटकर $10 प्रति बैरल रह गया है। आज, रूस प्रति बैरल तेल की बिक्री से $60 से $70 कमाता है। यदि इन राजस्वों को $40 से $50 प्रति बैरल तक घटाया जाता है, तो इससे रूसी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ सकती है।

रूस की ऊर्जा से होने वाली निरंतर आय का कारण पश्चिमी देशों के निर्णय हैं। 2022 में, वैश्विक तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं और अमेरिकी मुद्रास्फीति 9% से अधिक हो गई। वाशिंगटन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने अपने आर्थिक प्रतिबंधों से रूसी ऊर्जा को इसलिए बाहर रखा क्योंकि उन्हें डर था कि रूसी तेल निर्यात में रुकावट से वैश्विक कीमतें बढ़ेंगी और उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। यह डर तब भी सामने आया जब G-7 ने तेल मूल्य कैप बनाया। रूसी निर्यात को प्रतिबंधित करने के बजाय, इस कैप ने एक जटिल और लीक होने वाली योजना का उपयोग किया ताकि रूस की तेल कीमतें कम की जा सकें, लेकिन उसकी आपूर्ति वैश्विक बाजारों में जारी रहे। इस योजना में शिपिंग बीमा और वित्तपोषण में पश्चिमी प्रभुत्व का उपयोग किया गया ताकि रूसी निर्यातक जो इन सेवाओं का उपयोग करते हैं, वे कैप के नीचे बेचने के लिए मजबूर हों। यह कुछ महीनों तक काम करता रहा, लेकिन जैसे-जैसे रूस ने पश्चिमी सेवाओं से बचने के लिए टैंकरों का एक छाया बेड़ा तैयार किया, उसने कैप से बचने में सफलता प्राप्त की।

रूसी अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से विकृत हो चुकी है क्योंकि युद्ध के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आज पश्चिमी देशों को इतना संयम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोजोन में मुद्रास्फीति लगभग 2% तक गिर गई है, और तेल बाजारों में आपूर्ति बढ़ रही है जबकि वैश्विक मांग कमजोर पड़ रही है, जिससे कीमतें कम हो रही हैं। तेल $70 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, और अगर ट्रंप ने अपने वादे के अनुसार अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया, तो कीमतें और भी गिर सकती हैं। यदि पश्चिमी देशों के आक्रामक प्रतिबंधों के कारण रूसी कच्चे तेल का निर्यात प्रति दिन एक मिलियन बैरल (रूस के वर्तमान निर्यात का लगभग एक-पांचवां) तक कम हो जाता है, तो इससे 2022 की तरह वैश्विक आर्थिक आपदा नहीं आएगी। और

चूंकि रूस को अपने युद्ध प्रयासों को चलाने के लिए ऊर्जा राजस्व की सख्त जरूरत है, इसलिए यह संभव नहीं है कि वह पश्चिम से बदला लेने के लिए तेल निर्यात को रोक देगा।

रूसी हथियार प्रणालियों के लिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता एक और महत्वपूर्ण कमजोर बिंदु है। जनवरी 2024 में किए गए यरमाक-मैकफॉल अंतरराष्ट्रीय कार्य समूह और कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अध्ययन के अनुसार, यूक्रेन में युद्ध के मैदान में पाए गए रूसी हथियारों के 95% विदेशी घटक पश्चिमी देशों से आए थे। अकेले अमेरिकी कंपनियों से प्राप्त घटक 72% थे। ये प्रतिबंधित सामान चीन और हांगकांग के रास्ते रूस तक पहुंचते हैं। अगर पश्चिमी निर्यात नियंत्रणों को कड़ा किया जाता है, तो रूस को अपनी सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को महंगी तरीके से पुनर्संयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे चीनी तकनीक और घटकों को अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि निम्न स्तर की होती है। इससे युद्ध के मोर्चे पर हथियारों की आपूर्ति में बाधाएं और कमी पैदा हो सकती है।

वाशिंगटन डीसी में रूसी संघ के दूतावास के बाहर एलेक्सी नवलनी के लिए एक स्मारक की देखभाल करती एक रूसी महिला। जो बाइडेन प्रशासन ने एलेक्सी नवलनी की मौत के बाद रूस के खिलाफ 500 से अधिक प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें ऊर्जा राजस्व को लक्षित किया गया।

यूरोप के विकल्प

यूरोप के पास रूस पर आर्थिक दबाव डालने के अपने तरीके हैं, यहां तक कि अगर ट्रंप पुतिन के खिलाफ नरम रुख अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम नए रूसी शैडो टैंकरों की पहचान कर सकते हैं और उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ताकि तेल मूल्य कैप को लागू रखा जा सके। यूरोप के पास एक भौगोलिक कार्ड भी है। रूस का कच्चा तेल उसके बाल्टिक तट से डेनमार्क जलडमरूमध्य के रास्ते और काले सागर से जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के रास्ते निर्यात होता है। ये जहाज अक्सर बिना निरीक्षण और उचित तेल फैलाव बीमा के गुजरते हैं। यदि पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति और एक बड़ा गठबंधन हो, तो डेनमार्क, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे तटीय देशों, संभवतः नाटो समर्थन के साथ, इन टैंकरों का निरीक्षण कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका बीमा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इससे रूस को अपनी तेल निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पश्चिमी बीमा और टैंकरों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो केवल तब उपलब्ध होंगे जब वह मूल्य कैप के नीचे बेचे।

रूस का गैस क्षेत्र भी कमजोर है। राज्य-नियंत्रित ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम, जो कभी रूस का ताजमहल था, ने 2023 में $7.3 बिलियन का भारी नुकसान दर्ज किया।

रूस का गैस क्षेत्र भी कमजोर है। राज्य-नियंत्रित ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम, जो कभी रूस का ताजमहल था, ने 2023 में $7.3 बिलियन का भारी नुकसान दर्ज किया, क्योंकि वह यूरोपीय पाइपलाइन निर्यात को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो 2021 में 154 बिलियन क्यूबिक मीटर से घटकर 2023 में 27 बिलियन रह गया। यूरोपीय संघ को रूसी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो अभी भी उसके आयात का 20 प्रतिशत है। यूरोपीय देश अमेरिकी LNG से खोई हुई आपूर्ति की भरपाई कर सकते हैं, जिसे ट्रंप अमेरिकी निर्यात पर बाइडन की सीमा को हटा कर सुविधाजनक बना सकते हैं—यह एक ऐसा समझौता है जिसे ट्रंप स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।

बिना अतिरिक्त दबाव के रूस के पास 2025 में खेलने का कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। रूस में ड्यूल-यूज वस्तुओं को रोकने के लिए, यूरोपीय संघ को एक केंद्रीकृत एजेंसी स्थापित करनी चाहिए, जो सदस्य देशों में निर्यात नियंत्रण प्रवर्तन को मजबूत करे। इसके अलावा, उसे मौजूदा तंत्रों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण यूरोपीय औद्योगिक सामानों, जैसे स्वचालित मशीनरी, की बिक्री को तीसरे देशों में रोकना चाहिए। इन वस्तुओं का निर्यात कजाखस्तान और तुर्की जैसे देशों में हाल के वर्षों में बढ़ा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये बिक्री मार्ग प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर का समर्थन कर रहे हैं।

अंत में, यूरोपीय संघ इस तथ्य का फायदा उठा सकता है कि इसके पास 2022 के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा फ्रीज किए गए रूस के केंद्रीय बैंक के अधिकांश $300 बिलियन के संपत्ति हैं। यूरोपीय संघ इन संपत्तियों में से कुछ को जब्त कर सकता है और उनका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के लिए अतिरिक्त अमेरिकी सैन्य आपूर्ति को फंड करने के लिए कर सकता है। ट्रंप यूरोपीय भुगतान के लिए अमेरिकी हथियारों की खरीद का श्रेय ले सकते हैं, और आवश्यक अमेरिकी सैन्य सहायता की निरंतर आपूर्ति यूक्रेन को संघर्ष में बनाए रख सकती है।

ट्रंप फैक्टर

इन सभी कदमों का सब्सटेंस और ऑप्टिक्स ट्रंप को आकर्षित करेंगे। अमेरिकी प्राकृतिक गैस निर्यात बढ़ाने से अमेरिकी उत्पादकों को मदद मिलेगी और ट्रंप को यूरोप के साथ वार्ता में एक जीत हासिल करने का अवसर मिलेगा। यही स्थिति अमेरिकी हथियारों की यूरोपीय खरीद सुनिश्चित करने की है। ट्रंप यूरोप को यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए दबाव डालने में सफलता का दावा कर सकते हैं, जैसा कि बाइडन ने नहीं किया।

ड्यूल-यूज प्रौद्योगिकी पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों को मजबूत करना भी ट्रंप के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करेगा। यह उन क्षमताओं का निर्माण करेगा, जिन्हें ट्रंप अन्य अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों, जैसे चीन और ईरान, को पश्चिमी सैन्य घटकों के शिपमेंट को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन इस प्रयास को और बढ़ा सकता है, जो उद्योग और सुरक्षा के Bureau of Industry and Security को अतिरिक्त फंड प्रदान करने और उस एजेंसी की OFAC के साथ समन्वय को बेहतर बनाने के द्वारा किया जा सकता है।

अंततः, रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध मशीन पर दबाव डालना सबसे किफायती तरीका है जिससे ट्रंप वह हासिल कर सकते हैं जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं: रूस और यूक्रेन के बीच एक स्थिर समझौता, जिसे वे अधिकारिक रूप से श्रेय ले सकें। मास्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना, कीव के लिए सैन्य समर्थन को नाटकीय रूप से बढ़ाने से कहीं कम जोखिमपूर्ण है, और बिना अतिरिक्त दबाव के रूस के पास 2025 में कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। अगर ट्रंप मास्को को उचित युद्धविराम शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो उनकी चुनावी जीत वह चमत्कार नहीं होगी जिसकी पुतिन को उम्मीद थी।

विलुप्त होती परछाइयाँ

गिद्धों के बिना बिखरता संतुलन

मनोज कुमार

कभी भारत की आकाशगंगा का हिस्सा रहे गिद्ध आज लगभग विलुप्त हो चुके हैं। एक समय था जब आसमान में गिद्धों का विशाल झुंड मंडराता दिखता था, जो मवेशियों के शवों की तलाश में निकलता। वे हमारे वातावरण के साफ-सफाई के नायक थे, मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों और संक्रमण को फैलने से रोकते थे। लेकिन आज उनकी कमी का प्रभाव इंसानों पर भी पड़ रहा है, जो किसी त्रासदी से कम नहीं है।

गिद्धों की संख्या में अचानक आई इस गिरावट की मुख्य वजह एक दवा रही। 1990 के दशक के मध्य में मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक सस्ती दर्द निवारक दवा 'डाइक्लोफेनाक' ने गिद्धों की आबादी को खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाई। इस दवा से इलाज किए गए पशुओं के शव खाने के बाद गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। देखते ही देखते 5 करोड़ गिद्धों की संख्या लगभग शून्य पर पहुंच गई।

इस घटना के दूरगामी परिणाम सामने आने लगे। गिद्धों के बिना आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने लगी, जो कि मवेशियों के शवों को साफ नहीं कर पाते थे। इसका सीधा असर इंसानों के स्वास्थ्य पर पड़ा। गिद्धों की कमी से बीमारी और बैक्टीरिया फैलने लगे, जिनसे हर साल लगभग एक लाख से अधिक लोगों की मौत होने लगी। इन मौतों के पीछे रेबीज़ जैसी बीमारियों का फैलना भी शामिल था, क्योंकि आवारा कुत्तों के जरिए यह संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था।

गिद्धों के बिना, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बिगड़ गया। गिद्धों की गैर-मौजूदगी ने हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर भारी बोझ डाल दिया, जिससे पानी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई और स्वच्छता की समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। इन घटनाओं के चलते मानव मृत्यु दर में भी वृद्धि देखने को मिली, खासकर उन इलाकों में जहां पहले गिद्धों की आबादी अच्छी थी। यह आंकड़ा भयावह था—गिद्धों की कमी के कारण देश को हर साल 69 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। प्रकृति की यह आपदा एक गंभीर संदेश देती है कि हम पर्यावरण के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। गिद्ध जैसे जीव हमारे जीवन के लिए अनमोल हैं। उनके बिना हमारा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है, और इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस संकट ने यह साबित कर दिया है कि वन्यजीवों का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

हालांकि, उम्मीद अभी बाकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक टाइगर रिज़र्व में 20 गिद्धों को पालकर छोड़ने की कोशिश की गई है, जिन पर सैटेलाइट टैग्स लगाए गए हैं। यह पहल इस बात का संकेत है कि हम गिद्धों की आबादी को फिर से बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में भी हाल के सर्वेक्षणों में 300 से अधिक गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो उम्मीद की एक किरण है। लेकिन यह सफर लंबा है, और गिद्धों को पुनर्जीवित करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है।

यह कहानी सिर्फ गिद्धों की नहीं है, यह मानवता और पर्यावरण के बीच उस अदृश्य धागे की है, जिसे हमें समझना और संजोना बेहद जरूरी है।

अभिनय के महापुरुष

से एक भावपूर्ण मुलाकात

दीप्ति बचपन से ही उनकी बेहतरीन फ़िल्में जैसे श्री 420 और जागते रहो देखते आ रही थीं। जब उन्होंने पहली बार जागते रहो देखी थी, तब वह एक बच्ची ही थीं। यह एक ऐसी फ़िल्म थी जिसने मानवीय लालच और करुणा को दर्शाया था और जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया था।

1970 के दशक के प्रारंभ में, एक युवा दीप्ति नवल अपने घर से बहुत दूर, न्यू यॉर्क के हंटर कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थीं। एक ऐसी जगह, जहां भारतीय संस्कृति और अपनी मातृभूमि से दूरी का अहसास होता था, दीप्ति ने अपनी जड़ों से जुड़ी रहने के लिए एक खास कदम उठाया। उन्होंने एक रेडियो शो की मेज़बानी शुरू की, जिसका नाम था 'रंग महल'। इस शो में वह पुराने और मधुर हिंदी गाने बजाती थीं, जिन्हें वह बचपन से सुनती आई थीं और जिनसे उन्हें गहरा लगाव था। यह शो न्यू यॉर्क में भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया, जो उन्हें अपनी मातृभूमि की याद दिलाता था। यहां, विदेशी धरती पर, यह गाने और संगीत भारतीयों के लिए घर की यादों का एक माध्यम थे, और दीप्ति के लिए यह एक तरीका था, अपने समुदाय से जुड़ने का।

दीप्ति का सपना था कि वह न्यू यॉर्क आने वाले प्रसिद्ध भारतीय सेलेब्रिटीज़ को अपने शो में आमंत्रित करें। उन्होंने अपनी इस चाहत को पूरा करने का पहला कदम बढ़ाया, और उनका पहला मेहमान कोई और नहीं, बल्कि महान अभिनेता सुनील दत्त थे। उस समय दीप्ति बहुत घबराई हुई थीं, क्योंकि वह इस महान अभिनेता के सामने इंटरव्यू देने जा रही थीं। लेकिन सुनील दत्त साहब की दयालुता और सादगी ने दीप्ति को सहज बना दिया। वह उनकी घबराहट को महसूस कर गए और माइक उठाकर इंटरव्यू को एक दोस्ताना और गर्मजोशी भरी बातचीत में बदल दिया। उन्होंने दीप्ति से जीवन के सरल, पर महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की, और धीरे-धीरे उनकी घबराहट कम हो गई। यह अनुभव दीप्ति के लिए न केवल एक सीखने का पल था, बल्कि सुनील दत्त साहब की दयालुता और गर्मजोशी ने उनके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी।

दीप्ति के आत्मविश्वास में जबर्दस्त वृद्धि हुई, और जब राज कपूर न्यू यॉर्क आए, तब दीप्ति ने उनके साथ मिलने का सपना सच होता हुआ महसूस किया। वह बचपन से ही राज कपूर की फिल्मों की दीवानी थीं। श्रृंगारिक फिल्में जैसे 'श्री 420' और 'जागते रहो' ने उनके मन में भारतीय समाज और उसकी समस्याओं के बारे में एक गहरी समझ बनाई थी।

शर्मिला टैगोर की बेमिसाल यात्रा: 'बुरी लड़की' से लेकर सम्मानित आइकन तक

शर्मिला टैगोर, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी चमचमाती सितारा, जिन्होंने 'बुरी लड़की' के टैग को धूम मचाते हुए एक दमदार जगह बनाई, ने अपने सफर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने समाजिक मान्यताओं को चुनौती दी और फिल्म इंडस्ट्री में एक स्वतंत्र महिला के रूप में कदम रखा, तो उन्हें 'बुरी लड़की' का दर्जा मिल गया। शर्मिला ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, 'मुझ पर कीचड़ फेंका गया था, मैं तो एक समाजिक संदिग्ध बन गई थी।' यह वो समय था जब पुरुष कलाकारों को पूजा जाता था और महिलाओं को सिर्फ जज किया जाता था। शर्मिला ने अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया।

सोनाक्षी सिन्हा की उम्रदराज़ अभिनेता को करारा जवाब!

सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में एक राउंडटेबल पर अपनी बात खुलकर रखी और बताया कि एक उम्रदराज अभिनेता ने उन्हें इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह उनसे 'ज्यादा उम्र की' लग रही थीं! वहीं, जब वह महिलाओं से 30 साल छोटी उम्र की हीरोइनों के साथ रोमांस करते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती। सोनाक्षी ने इस पर दोहरा मापदंड उजागर करते हुए कहा, 'उन्हें उम्र को लेकर ताने नहीं मिलते, न ही उनकी लुक्स, पेट या पतले बालों पर सवाल उठते हैं। महिलाएं हमेशा ही आलोचनाओं का सामना करती हैं।

राधिका आप्टे की प्रेग्नेंसी सरप्राइज: कोई हादसा तो नहीं, फिर भी है एक बड़ा झटका!

राधिका आप्टे की प्रेग्नेंसी की कहानी उतनी ही मसालेदार है जितनी कि हैरान करने वाली। 'यह कोई हादसा नहीं था, लेकिन हम सच में इसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहे थे,' राधिका ने यह खुलासा किया, यह मानते हुए कि खुद को अच्छे से जानने वाली एक प्लानर महिला भी इस खबर से चौंक गई। अपने जीवन को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से चलाने वाली राधिका, जो ओव्यूलेशन ट्रैक करने की माहिर थीं, फिर भी यह खबर उन्हें चौंका गई। 'मैंने अगले दिन ही सबको बता दिया,' वह लंदन से जूम कॉल पर हंसते हुए कहती हैं। अंधाधुंध की स्टार का चेहरा उस व्यक्ति की तरह चमक रहा था, जो अपने जीवन के इस नए मोड़ को भी पूरी तरह से सहजता से स्वीकार कर चुकी है-मिचली, सूजन, और बाकी सबकुछ के बावजूद। हम अपने प्रेग्नेंसी के अजीब-अजीब अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे।

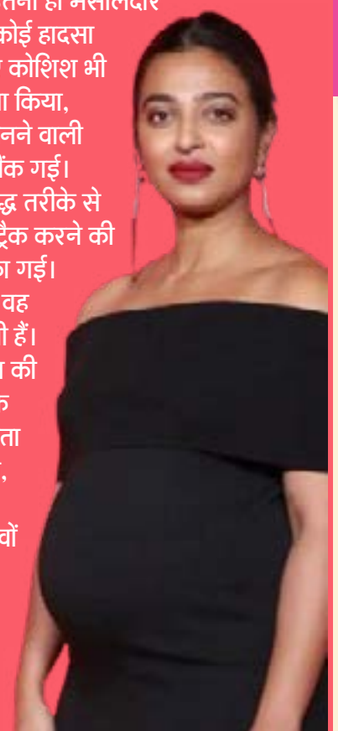

नयनतारा ने किया खुलासा

अज्ञानता ने ही रजनीकांत का सामना करने में मदद की!

नयनतारा ने अपने दक्षिण भारतीय सिनेमा में ड्रीम डेब्यू के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने बिना जानें ही सुपरस्टार रजनीकांत, Mammootty और Mohanlal जैसे दिग्गजों के साथ अपनी शुरुआत की। 'मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी,' नयनतारा ने यह स्वीकार किया, और यह भी बताया कि राजिनीकांत के मेगास्टार स्टेटस के बारे में उनकी अज्ञानता ने उनके पक्ष में काम किया, खासकर जब वे 'चंद्रमुखी' के पहले सीन में एक साथ थे। दिग्गजों से घिरी हुई नयनतारा ने बताया कि उनके इन सितारों की विशाल प्रसिद्धि से अनजान रहना उन्हें शांत रखने में मदद करता था, जिससे वह बेझिजक होकर बड़े फिल्ममेकर्स की मार्गदर्शन में अपने करियर को आगे बढ़ा पाई। ये था उनका डरहीन उत्थान का अजीब लेकिन असरदार रहस्य!

सलमान खान का 10 सेकंड में 'हां' कहना, एटली को चौंका दिया!

जब एटली ने वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' में सलमान खान के कैमियो का आइडिया casually बताया, तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सलमान खान महज 10 सेकंड में इसे मंजूरी दे देंगे! न कोई स्क्रिप्ट, न कोई सीन डिटेल्स—बस सलमान का एक त्वरित 'Done!' एटली ने स्वीकार किया कि वह इस गति से पूरी तरह चौंक गए थे, लेकिन सलमान का effortless एंट्री फिल्म के फिनाले में जबरदस्त धमाल मचाने वाली है। फैंस को अब एक 'solid mass scene' की उम्मीद है, जिसमें सलमान अपनी सिग्नेचर मैजिक दिखाते हुए धमाका करेंगे।

विज्ञान एवं तकनीक

संजय श्रीवास्तव

संभावनाओं से सबल यह साल

इंतज़ार में हैं उपलब्धियां

विज्ञान और तकनीक क्षेत्र के लिये 2025 एक विशेष वर्ष है। इस साल वह अब तक की अपनी प्रगति और गति आंकेगा और तद्नुरूप आगे के लक्ष्यपूर्ति की तैयारी भी करेगा। विज्ञान और तकनीक के लिये यह वर्ष आकलन, पूर्वाकलन, प्रदर्शन, विश्लेषण, शोध, विकास, आविष्कार, अन्वेषण, अनुप्रयोग, रणनीति निर्माण तथा अंतरराष्ट्रीय प्रयासों एवं संभावित राष्ट्रीय उपलब्धियों से परिपूर्ण रहने वाला है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, व्यवस्थाओं, बाज़ार का डिजिटलकरण, सेमीकंडक्टर, माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर, ब्लॉकचेन और कंप्यूटिंग लैंग्वेज, स्पेस, डिफेंस, रोबोटिक्स, अक्षय ऊर्जा, तकनीकी नवाचार तथा डेटा साइंस की उपलब्धियां खबरों में रहने वाली है। देश में तकनीक विकास का एक नजारा साल की शुरुआत में महाकुंभ के दौरान दिखेगा जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा बरास्ते तकनीक समूची दुनिया तक पहुंचेगा। 45 करोड़ से अधिक लोग मानवीय निगरानी के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीपीएस और स्ट्रीमिंग तकनीक पर आधारित सर्विलांस का व्यावहारिक कमाल देखेंगे। शौचालयों में सफाई की रियल-टाइम मॉनिटरिंग से लेकर साधु संतों के लाइव कार्यक्रम और सेवाओं की तत्काल अपडेट्स के साथ मेले के कैंपों तक की थ्रीडी खबर रखने वाले, प्रशासन और जनता के बीच तेजी से संपर्क साधने में मददगार ऐप प्रयागराज में आध्यात्मिकता और तकनीकी आधुनिकता के अद्भुत संगम का दर्शन कराएंगे। आस्था में

2025

विज्ञान के दर्शन से ठीक पहले 11 और 12 जनवरी 2025 को सभी उम्र के लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में आयोजित भारत विज्ञान महोत्सव, विज्ञान में आस्था का दर्शन कराएगा। महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, आम जनता को एक साथ लाता है इसकी सफलता देश में वैज्ञानिक माहौल का बैरोमीटर होगा। ऐसे में इस साल यह देखना दिलचस्प होगा कि विज्ञान और तकनीक जिस रफ्तार से देश में जगह बनाएगी क्या समाज भी उसी अनुपात में अपनी तार्किक और वैज्ञानिक सोच तथा तकनीक समझ में उल्लेखनीय बढोतरी कर सकेगा?

आज तकनीक के तकरीबन सभी क्षेत्र में भारतीय नवप्रवर्तक उपस्थित हैं सो तकनीक नवाचार में इस साल आशातीत विकास दिखेगा। भारतीय नवाचार अर्थव्यवस्था 2014 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की पांच प्रतिशत थी जो 2022 में दस प्रतिशत हुई और अब सरकारी उम्मीद 2025-2026 तक इसके 20 फीसद तक पहुंचने की है। सरकार के दावे के हिसाब से 2025 में जीडीपी 5,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी यानी तकनीक क्षेत्र कुल 1,000 अरब डॉलर का होन चाहिए। लगभग आठ

प्रतिशत की दर से बढ रहे तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्र से इस साल यह उम्मीद थोड़ी अधिक तो है पर बेमानी नहीं। सभी जी-20 देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौशल और प्रतिभा के मामले में शीर्ष पर पहुंचने वाला भारत इस साल इसके जरिये अपने सकल घरेलू उत्पाद में 500 अरब अमेरिकी डॉलर जोड़ेगा। भारत का एआई बाज़ार 35 प्रतिशत चक्रवृद्धि के सालाना दर से बढ़ रहा है। यदि इसके 2027 तक 17 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है तो उपरोक्त आकलन में दम नजर आता है। जनरेटिव एआई की बढत 28 फीसदी सालाना की दर से बढ़ने की उम्मीद है, 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके 400 अरब डॉलर के योगदान के लक्ष्य की ओर का यह वर्ष प्रस्थान बिंदु बनेगा। देश डिजिटली स्किल्ड कर्मचारियों की आवश्यक संख्या में 9 गुना बढत आंक कर इस साल तत्संबंधी प्रयास करेगा। रक्षा सुरक्षा,बीमा, स्वास्थ्य, सेवा से लेकर शिक्षा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, खुदरा, अवसंरचना, दूरसंचार तक, हर जगह काम आने वाले डेटा साइंस का क्षेत्र 2025 में नई रुझान के साथ सामने आयेगा। विगत वर्ष इस क्षेत्र में 60 अरब का निवेश हुआ था, इस साल 80 अरब डालर की उम्मीद का ठोस आधार डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार से है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद इस बरस मुंबई, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु डेटा सेंटर विकास के मुख्य केंद्र बनकर उभरेंगे।

रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस तकनीक का उपयोग इस साल कई कमाल करेगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का उद्योग 20 प्रतिशत के चक्रवृद्धि विकास दर से इस साल सवा सौ अरब डालर पार कर जाए तो अचरज नहीं होगा। इस क्षेत्र में इस साल क्लाउड आर्किटेक्ट डिजाइन और ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट, वेब एप्लिकेशन बनाने की क्षमता की मांग बढेगी। अभी के पच्चीस करोड़ 5जी उपयोगकर्ता 2025 के मार्च तक 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। हालांकि बड़ी आबादी तक इसकी पहुंच नहीं हो पाएगी पर यह बढत 2025 के वित्तीय वर्ष में प्रति ग्राहक प्रति माह औसत इंटरनेट डेटा खपत को 20 जीबी से बढाकर 30 जीबी तक बढा देगा।

विगत कुछ वर्षों की तरह इस साल भी सर्वाधिक सुर्खियां इसरो ही बटोरेगा। वह 2025 में रेलवे, थल सेना, नौ सेना, संचार,इन फ्लाइट कनैक्टिविटी के अलावा गगनयान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए छह उपग्रहों के साथ कई सर्विलांस सेटेलाइट भी लांच करेगा। इसी साल मार्च में इसरो नासा के सहयोग से तकरीबन तीन टन वजनी निसार उपग्रह लॉन्च करेगा, तकनीकि वजहों से टलते जा रहे इस महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण में सफलता विभिन्न कारणों से अंतरिक्ष के वैश्विक क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसी साल इसरो का लूनर फ्लाईबाई की योजना है जिसमें गगनयान मिशन के तहत चयनित अंतरिक्षयात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजैना और फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है। इसके अलावा इसरो इस साल चांद से नमूने लाने वाले चंद्रयान चार के मिशन में जी जान से लगेगा। 2025 के आखीर तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 13 अरब डॉलर तक पहुंचेगी तो वजह बनेंगे इस क्षेत्र में लगातार बढते स्टार्टप और छोटे उपग्रहों के विनिर्माण तथा प्रक्षेपण सेवा की बढ़ती मांग। इसरो अगर अंतरिक्ष में तीन गगनॉट भेजेगा तो 2025 में ही डीप-सी मिशन के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हिंद महासागर में 6,000 मीटर की गहराई तक तीन यात्रियों वाला पहला मानव मिशन भेजने को तैयार है।

2025 में 55 फीसद भारतीय ग्रेजुएट वैश्विक रोजगार के योग्य हो जायेंगे, इंजिनियरिंग के ऐसे छात्रों में पिछले साल के मुकाबले 5 फीसद की बढोतरी होगी और विज्ञान के ग्रेजुएट पिछली साल से 7 फीसद बढकर 58 प्रतिशत पर ऐसी क्षमता हासिल कर लेंगे। महाराष्ट्र,कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्य योग्य प्रतिभाओं के केंद्र बनेंगे।

मौलिक विज्ञान पर आधारित नई तकनीकों के विकास से नवाचार, विकास, और कौशल आधारित नौकरियां पैदा होने की संभावनाओं के बीच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के अनुसार दुनिया भर के नियोक्ता उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2025 तक 2025 तक लाखों इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी ऐसे में कार्यबल में 16 फीसदी से लेकर 19 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है और भारत भी इससे प्रभावित होगा, इस बरस बेरोजगारी बेकाबू होगी। पर सबसे बड़ी और घातक आशंका इस क्षेत्र में जेनरेटिव एआई और अन्य तकनीक के जरिये डीपफेक की घटनाओं के बढने, ऑनलाइन भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से सार्वजनिक धारणा, जन भावना को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करने, सामाजिक स्थिरता और सामंजस्य को तकनीक के सहारे झूठ ,घृणा, भय एवं विनाशकारी पूर्वाग्रहों को फैलाने के लिए हथियार बनाने में बढोतरी की है। यदि समाज में बढते तकनीक विज्ञान के बरअक्स वैज्ञानिक चेतना नहीं बढती है, उनके तार्किक और विवेकशील व्यवहार में बढत नहीं दिखती है तो तमाम वैज्ञानिक और तकनीक विकास की खुशियों के बावजूद हमें इस साल चिंतित रहने के भी कुछ कारणों से दो चार होना पड़ सकता है।

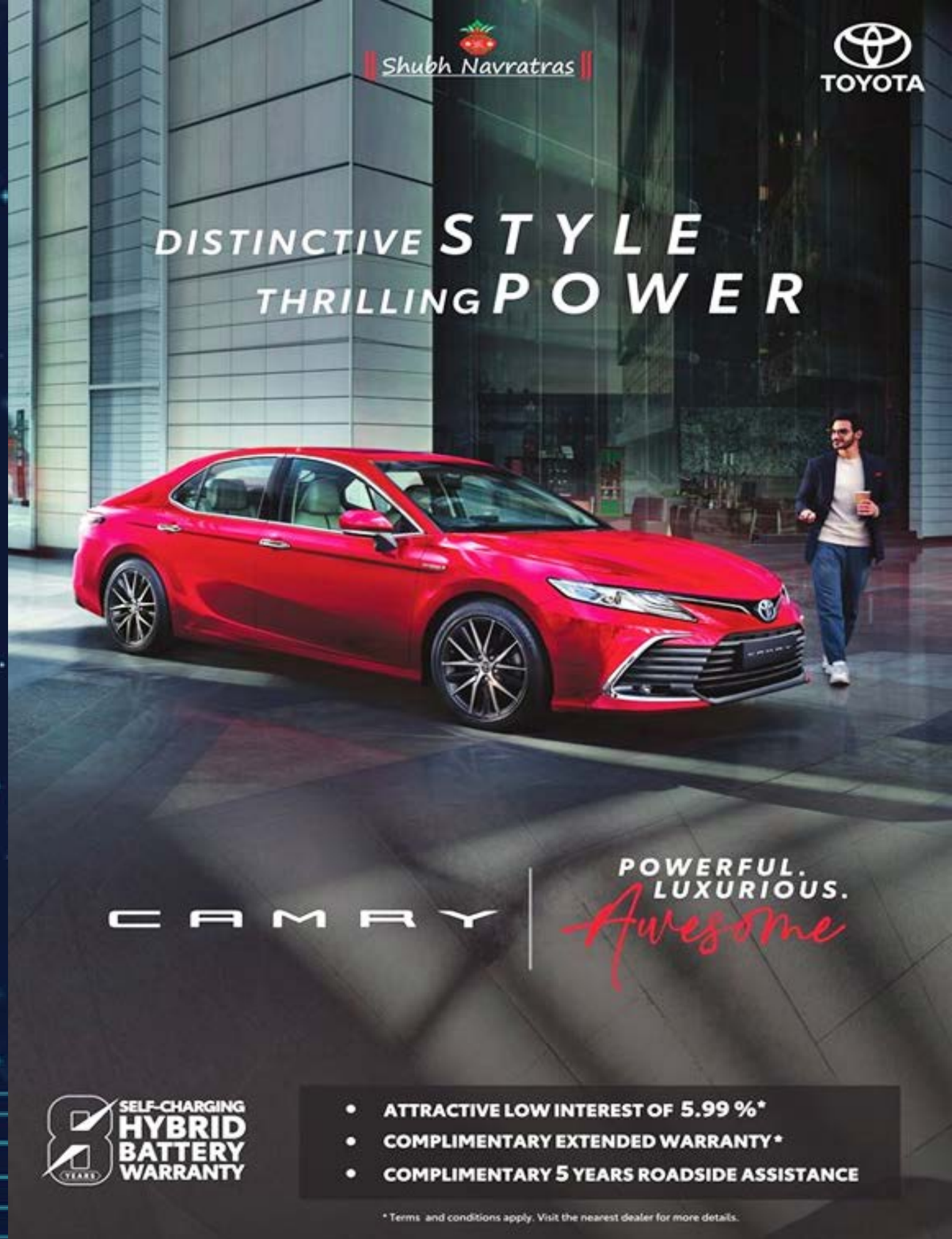

RNI TITLE CODE : DELENG19447

Experience it. Look at it from all angles. Check out the contours, the craftsmanship, the perfection of form and the waterfall...

Glamour ▪ Convenience ▪ Technology

MARC®
Bathing Luxury

MARC SANITATION PVT. LTD.

A-2, S.M.A. Co-op. Industrial Estate, G.T. Kamal Road, Delhi-110 033
Ph: 27691410, Fax: 011-27691445/27692295 E-mail: info@marcindia.com Website : www.marcindia.com